घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 186- शुक्रवार 08 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार.....

28 मंत्रियों ने ली शपथ,2 डिप्टी सीएम बनाए

पीएम ने पूर्व सीएम को बुलाया,हाथ पकड़कर पास लाए,नीतीश ने प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखा

पटना,07 मई 2026। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 22 दिन बाद गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया। मेगा इवेंट में नीतीश के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए। नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी(आर)-2, एचएएम और आरएएम से एक-एक मंत्री हैं। 25 मिनट चले इस कार्यक्रम में एक साथ 5-5 विधायकों ने शपथ ली है। पहली बार में निशांत कुमार,श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, लेसी सिंह, और दिलीप जायसवाल ने शपथ ली। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं। समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को अपने पास बुलाया। मंच पर उनसे हाथ मिलाया, इस दौरान नीतीश कुमार ने पीएम का कंधा पकड़कर हिला दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में सीधे राष्ट्रगान बजाया गया, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम् बजाया जाना था। दो बार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडेय इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, खबर है कि पार्टी में उन्हें बड़ी जगह दी जाएगी।

बीजेपी ने 3 चेहरों को ड्रॉप किया

सम्राट कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें 5 नए चेहरे हैं, वहीं तीन पुराने लोगों को इस बार मौका नहीं मिला। इनमें बीजेपी के सीनियर लीडर मंगल पांडेय,बेगूसराय के बछ्वाड़ा से विधायक सुरेंद्र मेहता और प. चंपारण से नारायण प्रसाद का नाम शामिल है। मंत्री पद नहीं मिलने के बाद मंगल पांडे को भाजपा संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पूर्व मंत्री नितिन नवीन की टीम में शामिल होंगे। खबर है कि मंगल पांडे को भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। साथ ही यूपी चुनाव में प्रभारी भी बनाए जा सकते हैं।

युवाओं को राजनीति में आना चाहिए : चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा,'आज से बिहार में नए युग की शुरुआत हो रही है, अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच,पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव और सम्राट चौधरी के युवा जोश वाली सरकार का एक अच्छा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है,युवाओं,निशांत कुमार को मौका मिला है। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और जाति,धर्म से ऊपर उठकर विकास होना चाहिए। '

सम्राट कैबिनेट में सभी जातियों का ख्याल रखा गया : जीवेश मिश्रा

बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा सम्राट कैबिनेट विस्तार की मैं सरकार को बधाई देता हूं। कैबिनेट में सभी जातियों, वर्गों को शामिल किया गया है।

नीतीश बोले...बिहार सुशासन की ऊंचाइयों को छूएगा

नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा- बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल विस्तार पर हार्दिक शुभकामनाएं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में सभी माननीय मंत्रीगण जनकल्याण और विकास कार्यों में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। बिहार विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नए मंत्रियों को आशीर्वाद दिया: मांझी

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, 'यहां सभी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नए मंत्रियों को आशीर्वाद दिया। सभी ने बिहार के विकास के लिए प्रार्थना की है।'

सोहराबुद्दीन शेख मामला : बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिसकर्मियों समेत सभी 22 आरोपितों को किया बरी...

मुंबई,07 मई 2026। गुजरात के कुख्यात अपराधी सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के महत्वपूर्ण फैसले को बरकरार रखते हुए 21 पुलिस अधिकारियों समेत सभी 22 आरोपितों को बरी करने का निर्णय बरकरार रखा है। सोहराबुद्दीन शेख के भाइयों की दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। यह मामला वर्ष 2005 का है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी जांच में दावा किया था कि सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति का अपहरण कर उनकी फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई थी। सीबीआई के अनुसार, 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद में सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर किया गया, जबकि कौसर बी की हत्या कर शव को ठिकाने लगाया गया था। इसके एक वर्ष बाद तुलसीराम प्रजापति की भी कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इस मामले में गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। वर्ष 2018 में विशेष सीबीआई अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सभी 22 आरोपितों को बरी कर दिया था। अदालत ने अपने 358 पृष्ठों के फैसले में सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत ने टिप्पणी की थी कि जांच एजेंसी ने निष्पक्ष जांच के बजाय पूर्वनिर्धारित कहानी के आधार पर राजनीतिक नेताओं को फंसाने का प्रयास किया। इस फैसले के खिलाफ सोहराबुद्दीन शेख के भाइयों रुबाबुद्दीन और नयाबुद्दीन ने बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

ईडी रेड के बीच नौवीं मंजिल से फेंके गए कैश सीएम के ओएसडी का करीबी बताया जा रहा

पंजाब,07 मई 2026। मोहाली के खरड़ में वेस्टर्न टावर्स सोसाइटी में आज इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की टीम ने आईटी सेक्टर में काम करने वाले एक व्यक्ति के घर पर दबिश दी। टीम को आता देख किसी ने रिहायशी टावर की नौवीं मंजिल से कैश से भरे बैग नीचे फेंक दिए। इनमें से एक बैग नीचे गिरते ही फट गया और उससे नोट निकलकर बाहर फैल गए। हालांकि, दूसरा बैग ठीक रहा, जिसे वहां पहले से गाड़ी के साथ खड़ा एक व्यक्ति मौका देखकर बैग को उठाकर भाग गया। टीम ने उसका पीछा किया, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। दूसरा बैग टीम ने जब्त कर लिया, जिसमें लगभग 21 लाख रुपये कैश मिला। टीम को बैग से 500-500 के नोटों की गड्डियां मिली हैं। फ्लैट में मौजूद व्यक्ति ने इन्हें लाल रंग के बैग में भरा और उस बैग को सफेद रंग के एक बैग में भरा और नीचे फेंका। इसके बाद भी बैग नीचे गिरते ही फट गया और नोटों की गड्डियां जमीन पर बिखर गईं। मामले की जांच चल रही है। अभी तक अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जिस टावर पर रेड चल रही है, वहां अब पुलिस ने लोगों की एंट्री रोक दी है। केंद्रीय एजेंसी के जवान मौके पर तैनात हैं। सीढ़ियों से लेकर टॉप तक फोर्स तैनात की गई है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि ये रुपए सीएम भगवंत मान के ओएसडी के हैं। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने दावा किया कि सीएम मान के ओएसडी राजबीर सिंह के करीबी नितिन गोहिल पर रेड हुई है। ओएसडी के ही रुपए हवा में उड़ते दिखे हैं।

चीन में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई दो पूर्व रक्षा मंत्रियों को मौत की सजा

बीजिंग,07 मई 2026। चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त अभियान के तहत एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। देश की अदालत ने पूर्व रक्षा मंत्री वेई फेन्हे और ली शांगफू को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई है। दोनों नेताओं के खिलाफ 2024 में जांच शुरू हुई थी, जो करीब दो साल तक चली और इसके बाद यह फैसला आया। 2018 से 2023 तक चीन के रक्षा मंत्री रहे,जबकि ली शांगफू को इसके बाद कुछ समय के लिए रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों ही नेता कभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाते थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइनाके प्रभावशाली सदस्य रहे हैं। जांच में सामने आया कि वेई फेन्हे पर ठेकेदारों से कमीशन लेने, महंगे गिफ्ट स्वीकार करने और अवैध संपत्ति अर्जित करने जैसे गंभीर आरोप थे।

सबरीमाला केस...हर धार्मिक प्रथा को कोर्ट में चुनौती ठीक नहीं इससे सैकड़ों केस आएंगे, धर्म-समाज पर असर पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,07 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर लोग धार्मिक प्रथाओं और धर्म के मामलों को संवैधानिक अदालत में चुनौती देने लगेंगे, तो इससे धर्म और सभ्यता पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि इससे सैकड़ों याचिकाएं आएंगी और हर रिवाज पर सवाल उठने लगेंगे। यह टिप्पणी नौ जजों की संविधान पीठ ने की, जो अलग-अलग धर्मों में धार्मिक आजादी के दायरे और महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। इसमें केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ा मामला और दाऊदी बोहरा समुदाय का केस भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 40 साल पुरानी जनहित याचिका की वैधता पर सवाल उठाए थे। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर हर व्यक्ति धार्मिक प्रथाओं पर सवाल उठाएगा, तो भारतीय समाज पर असर पड़ेगा, क्योंकि यहां

धर्म समाज से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने कहा, हर अधिकार पर सवाल उठेंगे-मंदिर खुलने या बंद होने तक के मामले कोर्ट में आएंगे। जस्टिस एम एम सुन्द्रेश ने कहा कि अगर ऐसे विवादों को लगातार अनुमति दी गई, तो हर व्यक्ति हर चीज पर सवाल उठाएगा। उन्होंने कहा कि इससे धर्म टूट सकते हैं और संवैधानिक अदालतों पर भी असर पड़ेगा। मामला दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ा यह मामला दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ा है। समुदाय के केंद्रीय बोर्ड ने 1986 में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें 1962 के फैसले को चुनौती दी गई थी। उस फैसले में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन एक्ट, 1949 रद्द कर दिया गया था। इस कानून के तहत किसी सदस्य को समुदाय से बाहर करना गैरकानूनी था। 1962 के फैसले में कहा गया था कि धार्मिक आधार पर किसी सदस्य को समुदाय से बाहर करना, समुदाय के धार्मिक मामलों के प्रबंधन का हिस्सा है। इसलिए 1949 का कानून संविधान के अनुच्छेद 26(बी) के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुधारवादी दाऊदी बोहरा समूह की ओर से वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कोर्ट में दलील दी कि अगर कोई प्रथा सामाजिक या निजी कारणों से जुड़ी है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए।

'118 विधायक लाओ, तभी होगी शपथ' अड़े तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र, विजय को दूसरी बार राजभवन से वापस भेजा

चेन्नई,07 मई 2026। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। टीवीके प्रमुख विजय आज एक बार फिर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। हालांकि राज्यपाल ने साफ संकेत दे दिए हैं कि केवल सबसे बड़ी पार्टी होने भर से सरकार बनाने का रास्ता आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल अपने रुख पर कायम हैं कि विजय को पहले विधानसभा में बहुमत का स्पष्ट आंकड़ा दिखाना होगा। राजभवन का मानना है कि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में अस्थिर सरकार का

जोखिम नहीं लिया जा सकता, इसलिए 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन साबित करना अनिवार्य होगा। दरअसल, 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया था।

ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव,बोले-आप हारी नहीं हैं

कोलकाता,07 मई 2026। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे और निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। अखिलेश ने कालीघाट स्थित ममता के निजी आवास पर भेंट की। इस दौरान उन्होंने ममता को शॉल ओढ़ाते हुए कहा, दीदी आप हारी नहीं हैं। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और सांसद डेरेक ओ ब्रायन मौजूद थे। आवास के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सभी को चुनाव में हुई बेइमानी के खिलाफ होना पड़ेगा,इस बार बहुस्तरीय माफियागिरी हुई है। उन्होंने कहा कि कोई सोच नहीं सकता था कि भाजपा, चुनाव आयोग, संगी-साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग इस तरह का चुनाव करेंगे। अखिलेश बोले, भाजपा ने जो बेईमानी उत्तर प्रदेश में की।

'मेरे पीए की हत्या इसलिए हुई क्योंकि मैंने ममता को हराया' शुभेंदु ने पीए की हत्या को बताया 'सोची-समझी साजिश'

नई दिल्ली,07 मई 2026। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि मैने पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हरा दिया, इसलिए उन्होंने मेरे सहयोगी चंद्रनाथ रथ को मार दिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द गुनहगारों को पकड़ा जएगा। सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि हमालवरों ने बहुत नजदीक से उन्हें गोली मारी है। जो भी हमलावर से उन्हें अच्छे से पता थी कि कहां गोली मारने से उनका तुरंत मौत दो जाएगी। अधिकारी ने बताया उनके शरीर से चार गोली निकली। यह हत्या पूरी

तरह से नियोजन करके की गई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम में बुधवार रात यह वारदात हुई। चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर चश्मदीदों ने कई गंभीर खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि यह हमला पूरी तरह सोची-समझी साजिश थी। हमलावर 4 से 5 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। उन्होंने चंद्रनाथ की कार का पीछा किया और दोहारिया इलाके में उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। चंद्रनाथ रथ भारतीय वायुसेना में सेवा देने के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगियों में से एक बन गए थे। 41 वर्षीय रथ मूल रूप से पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चांदपुर के रहने वाले थे। यह वह राजनीतिक क्षेत्र था।

पाकिस्तान में कोई आतंकी ठिकाना सुरक्षित नहीं 'ऑपरेशन सिंदूर' अंत नहीं शुरुआत : भारतीय सेना

जयपुर,07 मई 2026। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की नई रणनीतिक नीति का संकेत है। सेना ने दो टूक कहा कि अब पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना सुरक्षित नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई की शुरुआत है। जयपुर स्थित साउथ वेस्टर्न कमांड में गुरुवार को आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति,उपलब्धियों और उसके प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी। सेना ने इस अभियान को पिछले कई दशकों में पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का सबसे व्यापक और समन्वित सैन्य अभियान बताया। पत्रकार वार्ता में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के डिप्टी चीफ (ऑपरेशन) लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन ए. मिनवाला, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन एयर मार्शल अवधेश कुमार तथा डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि 'आत्मनिर्भर भारत' केवल नारा नहीं, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ाने वाली वास्तविक क्षमता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जा रहे 65 प्रतिशत से अधिक रक्षा उपकरण देश में ही निर्मित हो रहे हैं। राजीव घई ने कहा कि 7 मई, 2025 को शुरू हुए अभियान के दौरान भारतीय सेना ने सात और भारतीय वायु सेना ने दो प्रमुख आतंकी लक्ष्यों को निशाना बनाया था। इन कार्रवाइयों में आतंकवादी शिविरों को भारी क्षति पहुंची और 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई। उन्होंने दावा किया कि नियंत्रण रेखा पर बाद में हुई झड़पों में पाकिस्तान के 100 से अधिक सैनिक भी मारे गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने लंबे समय तक आतंकवादी ढांचे को सुरक्षित समझा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह धारणा पूरी तरह तोड़ दी। आतंकवादी कैंपों का स्थान बदलते रहने और उन्हें सीमा से भीतर खिसकाने की कोशिशों के बावजूद भारतीय सेना की पहुंच और क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजीव घई ने प्रसिद्ध शायर दुष्यंत कुमार की पंक्तियां उद्धृत करते हुए कहा 'सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। राजीव घई ने कहा कि भारत ने अपने स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद संघर्ष को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे युद्धों ने यह दिखाया है कि लंबे संघर्ष किस प्रकार विनाशकारी हो सकते हैं।

भारत ने संतुलित लेकिन तीव्र कार्रवाई के माध्यम से पाकिस्तान की जोखिम लेने की क्षमता और इच्छा दोनों को प्रभावित किया। एयर मार्शल अवधेश कुमार ने कहा कि भारत हमेशा 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत में विश्वास करता है, लेकिन जब शांति की इच्छा को कमजोरी समझा जाए और संयम को निष्क्रियता माना जाए।

पश्चिम बंगाल में राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा भंग की

कोलकाता में आज भाजपा विधायक दल की बैठक

कोलकाता,07 मई 2026। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी कर दिया है। लोक भवन, पश्चिम बंगाल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी किया गया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा को 7 मई 2026 से प्रभावी रूप से भंग कर दिया गया है। यह कदम संवैधानिक प्रावधानों के तहत लिया गया है। लोक भवन की अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(बी) के तहत राज्यपाल को प्राप्त अधिकारों के आधार पर लिया गया है। इसी पश्चिम बंगाल में शनिवार को शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित सभी 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहयोगी दलों के अध्यक्ष और वरिष्ठ मंत्री शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इससे पहले, केंद्रीय पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में शुक्रवार शाम चार बजे विधायक दल

की बैठक में नेता का चयन होगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में परेड ग्राउंड में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। 9 मई को शपथ समारोह होगा। तृणमूल कांग्रेस के बंगाली अस्मिता के मुद्दे की प्रभावी रूप से हवा निकालने के लिए भाजपा ने शपथ ग्रहण के लिए रवींद्रनाथ टैगौर की 165वीं जयंती को चुना है।

संपादकीय

आत्ममंथन के बजाय आरोपों का सहारा

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बीच विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए का पूरा विमर्श पश्चिम बंगाल के इर्द-गिर्द सिमटता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित किया। ममता ने यहां तक कहा कि वे हार को साजिश का परिणाम मानती हैं। उल्लेखनीय है कि 2014 के बाद से हुए कई चुनावों में विपक्षी दलों ने अपनी हार के कारणों का ठोस आत्ममंथन करने के बजाय आरोपों की राह अधिक चुनी है।

2014 में भाजपा की बड़ी जीत के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा जोर-शोर से उठा, जो हर चुनावी हार के बाद समय-समय पर सामने आता रहा है। हालांकि 2017 में चुनाव आयोग द्वारा आयोजित'ईवीएम चैलेंज' में कोई भी दल मशीनों में छेड़छाड़ का दावा साबित नहीं कर पाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वीवीपैट प्रणाली को और व्यापक रूप से लागू किया गया, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगते ही रहते हैं।

बंगाल में बात ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों से भी आगे निकल गई है। अब विपक्षी दलों का आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने पहले गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआइआर के तहत लाखों मतदाताओं के वोट काटे और फिर चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों ने भाजपा के इशारे पर काम करते हुए चुनावी गड़बड़ी की। यदि चुनाव प्रक्रिया इतनी व्यापक रूप से प्रभावित की जा सकती थी, तो अन्य राज्यों तमिलनाडु या केरलम में अलग-अलग नतीजे कैसे आए? केरलम में तो कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है।

विपक्ष इस तथ्य को नकार देता है कि बंगाल में भाजपा की उपस्थिति कोई नई नहीं है। पहले जनसंघ और बाद में भाजपा वहां पैर जमाने की कोशिश सदैव करती रही। 2016 के विधानसभा चुनाव में उसे 10 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले थे, जो 2021 में बढ़कर 37.97 प्रतिशत हुए और अब 45.85 प्रतिशत। तृणमूल कांग्रेस के वोट 2021 के 48.02 प्रतिशत से घटकर 2024 में 40.80 प्रतिशत पर आ गए। 15 साल की एंटी इनकंबेंसी, भ्रष्टाचार के आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण के विरुद्ध हिंदू ध्रुवीकरण, महिलाओं की सुरक्षा और कांग्रेस, वाम दलों का तृणमूल के खिलाफ होना ममता की हार की वजहों में रहे।

चुनावी धांधली का आरोप नया नहीं है। तमाम प्रयासों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह दोषमुक्त कभी नहीं रही। दिलचस्प है कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को 9 फरवरी 1952 को एक पत्र लिखा था, मुझे समय-समय पर चुनावों के संचालन के तरीके के बारे में विभिन्न शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।.आज सुबह मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में शिकायत मिली कि कई स्थानों पर मतदान पेटियों को बदल दिया गया या उनके साथ छेड़छाड़ की गई। बाद के वर्षों में बिहार, तमिलनाडु, जैसे कई राज्यों में भी चुनावी गड़बड़ियां होती रहीं।

1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त बूथ लूट और हिंसा रोकने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहली बार कई चरणों में चुनाव कराए। राज्य में बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई। उस वक्त लालू यादव खुलकर टीएन शेषन के खिलाफ बोलते थे। बंगाल में चुनावी हिंसा की अति हो गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त बंगाल में चुनावी हिंसा में सात मौतें और करीब 2,652 लोग घायल हुए। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान तो 300 से ज्यादा हिंसक घटनाओं में 58 मौतें हुईं।

इन हालात में केंद्रीय बलों की मौजूदगी ने अगर मतदाताओं को भयमुक्त होकर वोट डालने के लिए प्रेरित किया तो इसे गलत कैसे कहा जा सकता है? क्या ये भी एक वजह नहीं है कि बंगाल में मतदान के पहले चरण में 93.19 और दूसरे चरण में 91.66 प्रतिशत वोट पड़े? इसमें कोई शक नहीं कि एसआइआर का क्रियान्यवन और बेहतर होना चाहिए था,पर विपक्षी दलों की एसआइआर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश सिर्फ एक नैरेटिव बनाने का ही दांव है, जिसका उन्हें लाभ कम और लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान अधिक है। बिहार में भी यही कोशिश हुई थी,जहां एसआइआर के बाद 65 लाख लोगों के नाम कटे थे,पर नाम जोड़ने के लिए औपचारिक आवेदन सैकड़ों में भी नहीं हुए। संभव है कि बंगाल में एसआइआर के चलते कुछ लोग मतदान से वंचित हुए होंगे,पर विपक्ष वास्तव में एसआइआर के मुद्दे पर चिंतित था,तो उसे बयानबाजी से आगे बढ़ना चाहिए था। यदि वह पांच-सात हजार प्रभावित लोगों को ही आगे कर देता, तो मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ जाता,पर केवल बयानबाजी होती रही। तथ्य यह भी है कि एसआइआर के तहत जहां अधिक नाम कटे, वहां भाजपा के साथ टीएमसी ने भी जीत हासिल की है।

लोकतंत्र में सवाल उठाना आवश्यक है,किंतु हर चुनावी हार को साजिश बताना खतरनाक प्रवृत्ति है। इससे न केवल संस्थाओं पर अविश्वास बढ़ता है, बल्कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भी भटकता है। विपक्षी दलों के लिए जरूरी है कि वे जमीनी मुद्दों, संगठनात्मक मजबूती और वैकल्पिक नीति का एजेंडा बनाएं। ईवीएम में गड़बड़ी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत जैसे आरोप जनता के गले नहीं उतरते।

संकट की घड़ी में दुनिया की संजीवनी है रेडक्रॉस

योगेश कुमार गोयल
नजफ्फगढ़,नई दिल्ली

रेडक्रॉस की स्थापना महान् मानवता प्रेमी जीन हेनरी डयूनेंट द्वारा की गई थी, इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष विश्वभर में 8 मई का दिन 'अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस' के रूप में मनाया जाता है और संस्था की गतिविधियों से आम आदमी को अवगत कराने के प्रयास किए जाते हैं। रेडक्रॉस की स्थापना वर्ष 1863 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसायटी दुनिया के सभी देशों में रेडक्रॉस आन्दोलन का प्रसार करने के साथ-साथ रेडक्रॉस के आधारभूत सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में भी कार्य कर रही है। 8 मई 1828 को जन्मे डयूनेंट 1859 में हुई सालफिरोनो (इटली) की लड़ाई में घायल सैनिकों की दुर्दशा देख बहुत आहत हुए थे क्योंकि युद्धभूमि में पड़े इन घायल सैनिकों के उपचार के लिए कोई चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। युद्ध मैदान में घायल पड़े इन्हीं सैनिकों के दर्दनाक हालातों पर अपने कड़वे अनुभवों के आधार पर उन्होंने 'मेमोरी और सालफिरोनो' नामक एक पुस्तक भी लिखी और 1863 में रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति 'आईसीआरआई' का गठन किया। डयूनेंट के सतत प्रयासों की बदौलत ही 1864 में जेनेवा समझौते के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस मूवमेंट' की स्थापना हुई।

डयूनेंट ने इटली में युद्ध के दौरान रक्तपात का ऐसा भयानक मंजर देखा था,जब चिकित्सकीय सहायता के अभाव में युद्धक्षेत्र में अनेक घायल सैनिक हृदयविदारक कष्टों से तड़प रहे थे। ऐसे घायलों की सहायता के लिए उन्होंने स्थायी समितियों के निर्माण की आवश्यकता को लेकर आवाज बुलंद की, जिसका असर भी दिखा। युद्ध में आहतों की स्थिति के सुधार के साधनों का अध्ययन करने के लिए उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया। 1863 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में रेडक्रॉस के आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए गए तथा रेडक्रॉस आन्दोलन का विकास करते हुए आहत सैनिकों और युद्ध पीड़ितों की सहायता संगठित करने हेतु दुनियाभर के सभी देशों में राष्ट्रीय समितियां बनाने पर जोर दिया गया। नेपोलियन तृतीय के हस्तक्षेप के चलते अंतर्राष्ट्रीय समिति 'स्विस फेडरल काउंसिल' को 8 अगस्त 1864 को जेनेवा में सम्मेलन बुलाने के लिए राजी करने में सफल हुई,जिसमें

26 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन के चलते जेनेवा अधिवेशन हुआ,जिसमें सुरक्षा के प्रतीक रेडक्रॉस वाले सफेद झंडे पर स्वीकृति की मोहर लगाई गई,जो आज समस्त विश्व में रेडक्रॉस का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। शुरूआती दौर में रेडक्रॉस की भूमिका युद्ध के दौरान बीमार और घायल सैनिकों,युद्ध करने वालों और युद्धबंदियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना तथा उन्हें उचित उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने तक ही सीमित थी किन्तु अब इस संस्था के दायित्वों का दायरा लगातार विस्तृत होता जा रहा है।

मानवीय सेवा को समर्पित रेडक्रॉस ने प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अनेक घायल सैनिकों तथा नागरिकों की सहायता कर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया था। दुनिया के किसी भी भाग में जब भूकम्प, बाढ़, भू-स्खलन या अन्य किसी भी प्रकार की प्राकृतिक अथवा मानवीय आपदा सामने आती है तो सबसे पहले'अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसायटी' की टीमें वहां पहुंचकर राहत कार्यों में जुट जाती हैं। शांति और सौहार्द के प्रतीक के रूप में जानी जाने वाली इस संस्था ने अपने कर्मठ,समर्पित और कर्त्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवकों के माध्यम से न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फिलहाल 190 से भी अधिक देशों में 'रेडक्रॉस' संस्था सक्रिय है। भारत में 'भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी अधिनियम' के तहत वर्ष 1920 में रेडक्रॉस सोसायटी का गठन हुआ था और स्थापना के नौ वर्ष बाद इसकी सराहनीय गतिविधियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसायटी ने 'भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी' को मान्यता प्रदान की।

भारत में रेडक्रॉस की स्थापना के शुरूआती वर्षों में देश में रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते थे किन्तु वर्ष 1994 में रेडक्रॉस एक्ट में संशोधन करते हुए सोसायटी का पदेन अध्यक्ष महामहिम राष्ट्रपति को तथा सचिव केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बनाया गया। वर्तमान समय में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की देशभर में 750 से अधिक शाखाएं मानवता की सेवा में जी-जान से जुटी हैं। रेडक्रॉस एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था है, जो देश के किसी भी हिस्से में प्राकृतिक अथवा मानवीय आपदा के शिकार लोगों को बचाने व राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसमें शामिल होने वाले कर्मठ स्वयंसेवकों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। विश्वभर में रेडक्रॉस के करीब एक करोड़ सत्तर लाख स्वयं सेवक हैं। यही कारण है कि रेडक्रॉस दिवस को 'अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस' भी कहा जाता है।

रेडक्रॉस लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करती है और अपनी विभिन्न शाखाओं के जरिये देशभर में जगह-जगह रक्तदान शिविर लगाकर प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में रक्त एकत्रित करती है। देश में रक्त एकत्रित करने तथा वही रक्त जरूरतमंद लोगों के लिए सही समय पर उपलब्ध कराने का कार्य यह संस्था कई दशकों से लगातार कर रही है। वास्तव में रक्त इकट्ठा करने वाली यह विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी संस्था है, जिससे कैंसर,थैलेसीमिया,एनीमिया जैसी प्राणघातक बीमारियों से जूझ रहे हजारों लोगों की भी जान बचाई जाती हैं। रेडक्रॉस की पहल पर दुनिया का पहला ब्लड बैंक अमेरिका में 1937 में स्थापित हुआ था और वर्तमान में दुनियाभर के अधिकांश ब्लड बैंकों की देखरेख रेडक्रॉस तथा उसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा ही की जाती है। रेडक्रॉस देश के किसी भी भाग में मानवीय या प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों को बचाने तथा उन्हें राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। रेडक्रॉस का मुख्य उद्देश्य जीवन तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा करना एवं मानव मात्र का सम्मान सुनिश्चित करना है।

चुप चाप खड़े रहे खूनी

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

पुराने बरगद की जटाएं अब हवा में नहीं,दहशत में झूलती हैं। सुना है? पीपल ने पत्तों की खड़खड़ाहट में फुसफुसाहट घोली। क्या? शीशम की टहनियां कांपीं। इंसान आ रहा है, हाथ में उन्नति लेकर। बरगद ने गहरी सांस ली, जैसे कोई उड़िया वृद्ध हे भगवान कह रहा हो। उन्नति? पिछले बार तो इसे सड़क कहते थे, साल के पेड़ ने व्यंग्य से कहा। इस बार नाम बदल गया है, अब इसे स्मार्ट सिटी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की जगह वाई-फाई बहता है। पास खड़ा नन्हा नीम सिसका, दादी, क्या वाई-फाई से चिड़ियां घोंसला बनाएंगी? बरगद ने कड़वाहट से उत्तर दिया, नहीं बेटा,वहां सिर्फ गिद्ध बैठेंगे,जो कागजों पर दस्तखत करते हैं। पूरे जंगल में एक ऐसी टीस थी, जैसे किसी ने जीवित खाल उधेड़ दी हो। संवाद छोटे थे, पर हर शब्द कुल्हाड़ी की धार से भी ज्यादा पैना था। धूल से सने पत्तों पर अब ओस नहीं,बारूद की परत जमने लगी थी। अरे, तुम तो बड़े खुश दिख रहे हो? पलाश ने अपनी सूखी टहनियों को सिकोड़ते हुए कचनार से पूछा। कचनार ने फीकी हंसी हंसी,हां, मुझे कल सुंदरता का सर्टिफिकेट मिला है। पलाश चौंक गया, मतलब? मतलब यह कि मुझे काटा नहीं जाएगा,बस गमले में फिट कर दिया जाएगा। मेरी जड़ें अब पाताल नहीं छुएंगी, बस दो मग पानी की मोहताज रहेंगी। इसे तो प्रमोशन कहते हैं भाई! सागौन ने ठहाका लगाया,जो असल में एक रुदन था। जैसे उड़ीसा के गांवों में लोग भात की आस में आकाश ताकते हैं,हम अब टैंकर की आस में जिएंगे। जंगल की आत्मा अब एक ऐसी मंडी बन चुकी थी जहां हर पेड़ अपनी कीमत और अपनी मौत का दिन गिन रहा था। इंसानी आहट करीब आ रही थी, और हवा में विकास की गंध तीखी होने लगी थी।

वह देखो,चश्मा पहनकर संवेदना आ रही है,महुआ ने दूर सड़क पर रुकती सफेद जीप को देखकर कहा। जीप से कुछ लोग उतरे, जिनके हाथ

में फीते और फाइलें थीं। ये लोग हमारी छाती क्यों नाप रहे हैं? नन्हे नीम ने पूछा। बेटा, वे देख रहे हैं कि तुम्हारी अस्थियों से कितनी कुर्सियां बनेंगी,बरगद ने अपनी कोठर से आवाज निकाली। पर दादा, मैंने तो सुना था कि इंसान पेड़ों की पूजा करता है?हां, करता है! जब हम मर जाते हैं, तो वह हमारी लकड़ी पर घी डालकर अपनी स्वर्ग की राह रोशन करता है। व्यंग्य इतना गहरा था कि हवा भी शर्म से रुक गई। मते रक्षा करतु (मुझे बचाओ),नीम चिल्लाया। चुप कर,साल ने उसे डांटा, यहां प्रार्थनाएं नहीं, सिर्फ टेंडर सुने जाते हैं। तुम्हारी भाषा इन्हें समझ नहीं आएगी,इन्हें सिर्फ नोटों की कड़कड़ समझ आती है। शाम ढलते-ढलते जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। आज कोई पक्षी नहीं आया? कचनार ने पूछा। पक्षी समझदार हैं,उन्हें पता चल गया है कि यहां अब नेटवर्क ज्यादा है और नीड़ कम, बरगद ने अपनी अंतिम छाल सहेजते हुए कहा। सुना है, शहर में एक बड़ा उत्सव होने वाला है,शीशम ने सूचना दी। कैसा उत्सव? पर्यावरण दिवस! वहां वे प्लास्टिक के पौधों को पानी देंगे और हमारी तस्वीरों के सामने मोमबत्तियां जलाएंगे। अचानक दूर से एक भारी मशीन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। जंगल की जड़ों में एक कंपन हुआ, जैसे धरती को मिर्गी का दौरा पड़ा हो। तैयार हो जाओ,बरगद ने अपनी आंखें मूंद लीं, अब वे हमें मुक्ति देने आ रहे हैं। इस विकास के महायज्ञ में हमारी बलि ही तो मुख्य आहुति है। मशीनें करीब आईं,पर वे रुकी नहीं। वे जंगल को चीरती हुई आगे निकल गईं। पेड़ों ने राहत की सांस लेनी चाही, पर तभी देखा कि उन मशीनों के पीछे कुछ लोग फटेहाल कपड़ों में,हाथ में अपनी जमीन के कागजात लिए भाग रहे थे। वे लोग पेड़ों से लिपटकर रोने लगे। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? नीम ने एक बूढ़े आदिवासी से पूछा। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस अपनी फटी जेब से एक चेक निकाला। पेड़ों को लगा कि शायद ये लोग उन्हें बचाने आए हैं। तभी बरगद की नजर उस चेक पर पड़ी। उस पर किसी बड़े बैंक की मुहर थी और राशि लिखी थी–शून्य। सस्पेंस तब खुला जब बैंक की गाड़ी पीछे से आई। बैंक वालों ने पेड़ों को नहीं काटा, बल्कि उन बिलखते इंसानों को पैसे थमाए और कहा, ये लो अपनी जमीन और इन पेड़ों का मुआवजा। अब यहां शोक नहीं, गोल्फ कोर्स बनेगा।पेड़ हतप्रभ खड़े थे। उन्हें काटा नहीं गया था, उन्हें खरीदा गया था। अब वे पेड़ नहीं, प्रॉपर्टी थे। बैंक वाले पैसे दे चुके थे और अब वे पेड़ कुल्हाड़ी का नहीं, किस्त न भर पाने के डर से कांप रहे थे।

ससुराल से दूरी और पति पर पकड़ क्यों?

प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

विवाह में सियासत बंद करो, साझेदारी का समय आ गया

शादी कोई सत्ता-संघर्ष नहीं,बल्कि दो व्यक्तियों के बीच भरोसे,सम्मान और जिम्मेदारी का रिश्ता है। लेकिन हमारे समाज में कई बार विवाह को साझेदारी के बजाय नियंत्रण का खेल बना दिया जाता है,जहाँ एक पक्ष अपनी परंपराएँ थोपना चाहता है और दूसरा अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए कठोर रुख अपना लेता है। यही टकराव आगे चलकर झगड़े,दूरी और अविश्वास में बदल जाता है, और फिर लोग पूरे रिश्ते को ही दोष देने लगते हैं। असल समस्या रिश्ते में नहीं, बल्कि रिश्ते को समझने की सोच में होती है।

आज जो वैवाहिक तनाव दिखाई देता है,उसे केवल महिलाओं की सोच कहकर खारिज करना आसान है, लेकिन यह अधूरा विश्लेषण होगा। भारतीय परिवारों में लंबे समय तक पुरुष को निर्णयकर्ता और महिला को समर्पित भूमिका में रखा गया। इस ढाँचे में बहू से अपेक्षा की गई कि वह सब कुछ स्वीकार करे,चुप रहे,ढले और परिवार की परंपराओं को बिना सवाल के निभाए। दूसरी ओर,नई पीढ़ी की महिलाएँ शिक्षा,नौकरी,आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के कारण इस भूमिका को चुनौती देने लगी हैं। वे अब सिर्फ बहू बनकर नहीं रहना चाहतीं,वे व्यक्ति के रूप में सम्मान पाना चाहती हैं।

यही वह बिंदु है जहाँ पीढ़ियों का अंतर साफ दिखाई देता है। पहले विवाह का अर्थ था पति के घर में जाकर उसी व्यवस्था को अपनाना,चाहे वह व्यवस्था न्यायपूर्ण हो या नहीं। आज की स्त्री यह मानती है कि शादी के बाद भी उसका अपना व्यक्तित्व,उसका परिवार,उसके विचार और उसकी सीमाएँ बनी रहनी चाहिए। यह मांग अपने आप में गलत नहीं है। हर इंसान को अपने सम्मान और अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार है। समस्या तब शुरू होती है जब इस अधिकार को अड़ियलपन या विद्रोह समझ लिया जाता है।

दूसरी तरफ,कई पुरुष भी पुराने ढर्रे में फँसे रहते हैं। वे चाहते हैं कि पत्नी उनके परिवार में पूरी तरह घुल जाए, उनकी माता-पिता की हर बात माने,घर की हर परंपरा निभाए और किसी भी स्थिति में सवाल न उठाए। वे यह भूल जाते हैं कि शादी दो व्यक्तियों का मिलन है,न कि एक व्यक्ति का दूसरे पर अधिकार। जब पुरुष यह सोच रखता है कि पत्नी को बस समायोजन करना है, और उसे बदलने का अधिकार सिर्फ उसी के पास है,तब रिश्ते में असंतुलन पैदा होता है। यह असंतुलन धीरे-धीरे शंका,कटुता और दूरी में बदल जाता है।

ससुराल का रिश्ता तब तक मधुर रहता है जब तक उसमें सम्मान हो। सम्मान का अर्थ केवल औपचारिक आदर नहीं,बल्कि भावनात्मक स्वीकार्यता है। बहू से यह उम्मीद करना कि वह अपने माता-पिता,अपने संस्कार, अपने विचार और अपनी प्राथमिकताएँ छोड़ दे,वास्तव में एक प्रकार का भावनात्मक दबाव है। विवाह के बाद नया घर मिलना अलग बात है,लेकिन पुराने रिश्तों को काट देना अलग बात है। एक स्त्री एक ही समय में बेटी भी

रह सकती है, पत्नी भी रह सकती है और बहू भी। समस्या तब होती है जब उससे केवल बहू बनकर रहने की माँग की जाती है,और बाकी पहचानों को महत्व नहीं दिया जाता।

इसी तरह यह भी सच है कि कुछ मामलों में पत्नी भी रिश्ते को साझेदारी की बजाय नियंत्रण की लड़ाई बना देती है। वह पति को प्रेम,समझ और संवाद से नहीं,बल्कि दबाव,शिकायत और आरोप के माध्यम से चलाना चाहती है। ऐसा व्यवहार भी रिश्ते को कमजोर करता है। विवाह में यदि एक पक्ष हर बात पर हावी होने की कोशिश करे, तो दूसरा या तो टूटता है या प्रतिरोध में कठोर हो जाता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि गलती केवल पुरुषों की है या केवल महिलाओं की। समस्या उस मानसिकता की है जो विवाह को सहयोग की जगह शक्ति-संतुलन की लड़ाई बना देती है।

असल में, भारतीय समाज में विवाह पर कई परतें एक साथ काम करती हैं। प्रेम,परंपरा,जाति,परिवार, संपत्ति, प्रतिष्ठा और सामाजिक दबाव, सब मिलकर शादी को प्रभावित करते हैं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह बिना विरोध किए सब कुछ स्वीकार कर ले,अवास्तविक है। समाज बदल रहा है,शिक्षा बढ़ी है, आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है, और सूचना के साधन भी बढ़े हैं। अब लोग पुराने निर्णयों को बिना सवाल किए नहीं मानते। यही कारण है कि विवाह के भीतर संवाद की ज़रूरत पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि संवाद की जगह अक्सर आरोप, शिकायत और भावनात्मक दूरी ले लेती है।

कई घरों में समस्या पति-पत्नी के बीच कम और परिवार की हस्तक्षेपकारी भूमिका के कारण अधिक बढ़ती है। सास-ससुर, भाई-बहन, रिश्तेदार और समाज,सब मिलकर दंपति के निजी जीवन में राय देने लगते हैं। हर छोटी बात पर सलाह, तुलना और दखल रिश्ते को खोखला कर देती है। जब पति अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा नहीं होता, तब पत्नी को लगता है कि शादी के बाद उसका अपना कोई सहारा नहीं बचा। और जब पति को लगता है कि पत्नी उसके घर में आई है,इसलिए उसे पूरी तरह झुकना चाहिए,तब वह संवेदनशीलता खो देता है। ऐसे में दोनों ओर से दूरी बढ़ती है। रिश्ते में प्रेम कम और रणनीति अधिक दिखने लगती है। यह भी समझना होगा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता एक ही चीज़ नहीं हैं। किसी स्त्री का अपने सम्मान के लिए बोलना, अपने निर्णय लेना और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना स्वच्छंदता नहीं है। लेकिन यदि वह हर बात में टकराव को ही समाधान समझने लगे, तो रिश्ते में शांति नहीं रह सकती। इसी तरह पुरुष का परिवार के प्रति जिम्मेदार होना जरूरी है,लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर पत्नी पर एकतरफा शासन करना न्याय नहीं है। पति-पत्नी के संबंध में मर्यादा,संवेदना और सम्मान का संतुलन होना चाहिए। जब तक यह संतुलन नहीं होगा, तब तक शादी में तनाव बना रहेगा।

समाज को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज की महिला पहले जैसी चुप और सहने वाली नहीं रही। यह बदलाव बुरा नहीं है। यह सामाजिक विकास का संकेत है। जिस स्त्री ने शिक्षा पाई है, जो कमाती है, जो अपने अधिकार समझती है,वह अब हर बात पर समझौता नहीं करेगी। उसे यह भी एहसास है कि शादी का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि साझी जिंदगी है। इसी तरह पुरुष को भी यह समझना होगा कि पत्नी का सम्मान करना उसकी कमजोरी नहीं,बल्कि उसकी परिपक्वता है। जो पति अपनी पत्नी को बराबरी से देख सकता है, वही वास्तव में मजबूत है। जो पति अपनी पत्नी को दबाकर रखना चाहता है,वह ताकतवर नहीं,असुरक्षित होता है।

परिवारों के भीतर सबसे बड़ी जरूरत यह है कि रिश्तों को पदानुक्रम की तरह नहीं,बल्कि साझेदारी की तरह देखा जाए। बेटी को अपने घर में जो सम्मान मिला है, वही सम्मान बहू के रूप में भी मिलना चाहिए। पत्नी को पति के घर में अनुग्रह नहीं,अधिकार मिलना चाहिए। पति को भी केवल कमाने वाला नहीं,समझने वाला, सुनने वाला और जिम्मेदारी बाँटने वाला साथी बनना चाहिए। यह बात जितनी जल्दी समझ ली जाएगी,उतनी जल्दी वैवाहिक रिश्तों में तनाव कम होगा। विवाह का भविष्य दमन में नहीं, संवाद में है। डर में नहीं,भरोसे में है। आदेश में नहीं,समानता में है। आज जरूरत इस बात की है कि हम महिलाओं के बारे में सामान्यीकरण बंद करें। हर महिला एक जैसी नहीं होती। हर पुरुष भी एक जैसा नहीं होता। कुछ महिलाएँ सचमुच रिश्ते में हावी होने की कोशिश करती हैं,तो कुछ केवल सम्मान और सुरक्षा चाहती हैं। कुछ पुरुष सच्चे जीवनसाथी होते हैं,तो कुछ केवल अपनी इच्छा थोपना जानते हैं। इसलिए किसी एक वर्ग को दोषी ठहराना समाधान नहीं है। सही दृष्टि यह है कि हम रिश्तों को इंसानी स्तर पर समझें, न कि लिंग के आधार पर एकतरफा निष्कर्ष निकालें।

विवाह को बचाने के लिए सबसे पहले अहंकार को कम करना होगा। पति को यह स्वीकार करना होगा कि पत्नी उसकी संपत्ति नहीं है। पत्नी को यह समझना होगा कि पति को नियंत्रित करना प्रेम नहीं है। ससुराल को यह मानना होगा कि बहू कोई बाहरी वस्तु नहीं, परिवार की सदस्य है। और मायके को यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान दखल नहीं, धैर्य और संवाद है। जब तक हर पक्ष अपनी भूमिका को अधिकार और दबाव के रूप में देखता रहेगा, तब तक समस्या बनी रहेगी।

सच यह है कि आधुनिक विवाह में सबसे बड़ी चुनौती स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन की है। यदि स्वतंत्रता केवल अपने लिए चाही जाए और जिम्मेदारी दूसरे पर डाल दी जाए, तो रिश्ता नहीं चलेगा। यदि जिम्मेदारी केवल एक पक्ष से माँगी जाए और दूसरे पक्ष को छूट दी जाए, तो भी रिश्ता नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूरत साझी समझ की है। पति-पत्नी को एक-दूसरे के खिलाफ नहीं,एक-दूसरे के लिए खड़ा होना सीखना होगा। जब यह भावना बनेगी,तभी शादी का असली अर्थ वापस आएगा।

चिरई बर परई

सोमेश देवांगन
कबीरधाम,छत्तीसगढ़.

चिरई बर परई सुनइया मन ल एकदम साधारण बात लागत हवय,फेर एकर भीतर मं बहुत गहिरा बात छुपे हवय। चिरई मतलब छोटे-छोटे पंछी जेन मन हमरआस-पास फुदकथें,अउ परई मतलब पानी रखे वाला माटी के छोटे बर्तन। ये बात हमन ला सिखाथे कि सिरिफ अपन बर नई,बल्कि दूसर जीव-जंतु बर घलो सोचना जरूरी हवय।आज के समय मं जब गरमी दिन-ब-दिन बढ़त जावत हवय, जंगल कटत जावत हें,तालाब अउ नदिया सुखत जात हें, त ये छोटे-छोटे पंछी मन बर पानी मिलना मुस्किल लगत हवय। आदमी त अपन बर पानी के जुगाड़ कर लेथे नल, बोतल, कूलर, सब सुविधा हवय फेर ये चिरई चूरगुन मन कहां जाहीं...? ओमन घलो जिन्दा रहना चाहथें,ओमन ला घलो पियास लगथे। अइसने हालत मं चरई बर परई रखे के परंपरा एक बहुत सुंदर अउ जरूरी काम आय। जब हमन अपन घर के आंगन, छत, बाड़ी या खिड़की के पास एक छोटकन परई मं पानी भर के रखथन, त वो सिरिफ पानी नई होथे वो एक जीवन के सहारा बन जाथे। चिरई मन आवत हें, पानी पीथें, अपन पियास बुझाथें अउ फिर फुदक के उड़ जाथें। ये नजारा मन ला खुशी देथे अउ भीतर मं एक संतोष के भावना जागथे।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

नाबालिग आदिवासी बच्चियों से सामूहिक दुराचार मामला : गलत मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस का सीएमएचओ कार्यालय घेराव

कांग्रेस का आरोप-घटना दबाने की कोशिश,दोषी पुलिस अधिकारी और चिकित्सक को संरक्षण,3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 मई 2026
(घटती-घटना)।

सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वंदना में दो नाबालिग आदिवासी बच्चियों के साथ हुए कथित सामूहिक दुराचार मामले ने अब राजनीतिक और सामाजिक रूप से बड़ा रूप ले लिया है। मामले में कथित तौर पर गलत मेडिकल रिपोर्ट देने वाले चिकित्सक और प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोठीघर से रैली के रूप में निकले और नारेबाजी करते हुए सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मामले को दबाने और आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।

24 अप्रैल को हुई थी घटना, प्रारंभिक जांच पर उठे सवाल

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 24 अप्रैल को सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम वंदना में दो नाबालिग आदिवासी बच्चियों के साथ सामूहिक दुराचार की घटना हुई थी। घटना सामने आने के बाद प्रारंभिक स्तर पर थाना सीतापुर द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई शुरुआती मेडिकल जांच में चिकित्सक ने रिपोर्ट दी कि बच्चियों के साथ किसी प्रकार का अनाचार नहीं हुआ है। लेकिन बाद में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराए गए परीक्षण में दुराचार की पुष्टि हुई, जिसके बाद शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस का आरोप है कि इस विरोधाभासी रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि मामले को दबाने का प्रयास किया गया।

पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन का आरोप : कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने बताया कि 5 मई को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि संबंधित पुलिस अधिकारी का आचरण पॉक्सो एक्ट की धारा 21(1) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। कांग्रेस ने मांग की कि मामले की जांच सीतापुर थाना से हटाकर किसी सक्षम महिला पुलिस अधिकारी को सौंपी जाए, ताकि पीड़ित बच्चियों को निष्पक्ष न्याय मिल सके। हालांकि अब तक इस मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

'सुशासन नहीं, दुःशासन चल रहा' - बालकृष्ण पाठक : घेराव के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाठक ने राज्य सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में 'सुशासन' का दावा केवल दिखावा बनकर रह गया है। उन्होंने कहा, 'इतनी गंभीर घटना के बाद भी दोषी पुलिस अधिकारियों और गलत रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह साबित करता है कि सिस्टम अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। आदिवासी बच्चियों के साथ हुए अत्याचार को दबाने की कोशिश लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े करती है। '

कांग्रेस ने बनाई थी जांच समिति

घटना के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने पांच सदस्यीय जांच दल गठित कर पीड़ित बच्चियों और उनके परिजनों से मुलाकात की थी। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि जांच के दौरान पीड़ित परिवारों ने भय और दबाव के माहौल की जानकारी दी। कांग्रेस का कहना है कि बच्चियों ने जिस दर्दनाक घटना का सामना किया, उसके बावजूद प्रशासनिक तंत्र न्याय दिलाने के बजाय मामले को कमजोर करने में लगा हुआ है। नेताओं ने आरोप लगाया कि आदिवासी परिवार होने के कारण पीड़ित पक्ष को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

आदित्येश्वर सिंहदेव ने भी उठाई थी कार्रवाई की मांग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने भी इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों और चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार शिकायतों और ज्ञापनों के बावजूद अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जिस पुलिस अधिकारी ने प्रारंभिक स्तर पर मामले को दबाने का प्रयास किया था, उसी अधिकारी द्वारा अब भी जांच की जा रही है,जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

'जनता में भारी आक्रोश': अमरजीत भगत

पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि थाना सीतापुर और मेडिकल जांच करने वाले चिकित्सक की भूमिका को लेकर आमजन में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि छोटी बच्चियों के साथ हुए सामूहिक अनाचार जैसे जघन्य अपराध को दबाने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन करेगी।

तीन दिन में कार्रवाई का आश्वासन

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद सीएमएचओ कार्यालय की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया कि आगामी तीन दिनों के भीतर संबंधित चिकित्सक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कांग्रेस ने फिलहाल अपना घेराव और प्रदर्शन समाप्त कर दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो जिलेभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता

प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिला एवं ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारी,ब्लॉक अध्यक्ष, मोर्चा संगठन, मंडल अध्यक्ष, बूथ एवं वार्ड कमेटियों के सदस्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अमला भी मौके पर तैनात रहा।

फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती,शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण,बतौली पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 मई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दैहिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर बतौली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर सरगुजा पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में चर्चा हो रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता की वर्ष 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से बतौली निवासी विक्रम सिंह से पहचान हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और प्रेम संबंध स्थापित हो गया। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी विक्रम सिंह ने युवती से विवाह करने और पत्नी बनाकर रखने का भरोसा दिलाया।

शादी का वादा कर घर ले गया,बनाया शारीरिक संबंध

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 5 अक्टूबर 2022 को आरोपी उसे अपने साथ घर ले गया,जहां उसके मना करने के बावजूद जबरन शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी लगातार उसे शादी का भरोसा देता रहा और इसी भरोसे का फायदा उठाकर कई बार उसके साथ संबंध बनाता रहा। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक लगातार विवाह का प्रलोभन देकर उसका दैहिक शोषण किया। इस दौरान दोनों के बीच लगातार संपर्क बना रहा।

गर्भवती होने पर दवा देकर कराया गर्भपात

मामले में एक गंभीर आरोप यह भी सामने आया है कि मई 2025 में पीड़िता गर्भवती हो गई थी। आरोप है कि इसके बाद आरोपी विक्रम सिंह ने दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। पीड़िता का कहना है कि वह लगातार आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाती रही, लेकिन वर्ष 2026 आते-आते आरोपी ने उससे बातचीत बंद कर दी और विवाह करने से साफ इंकार कर दिया।

अंबिकापुर अग्निकांड में बड़ा फैसला : पटाखा भंडारण और भीषण आग मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

घनी आबादी में ज्वलनशील सामग्री रखने पर न्यायालय सख्त,जांच प्रभावित होने की आशंका भी जताई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 मई 2026
(घटती-घटना)।

शहर के बहुचर्चित अग्निकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय, सरगुजा ने आरोपी प्रवीण कुमार अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला थाना अंबिकापुर के अपराध क्रमांक 259/2026 से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रारंभिक रूप से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125, 270 एवं 287 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। बाद में जांच के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 324(6), 326(छ) बीएनएस तथा विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(ख)(द्व)(ख) भी जोड़ी गई।

राम मंदिर रोड की घटना ने खड़े किए कई सवाल

न्यायालयीन अभिलेखों के अनुसार 23 अप्रैल 2026 को राम मंदिर रोड स्थित एक दुकान में भीषण आग लग गई थी। आरोपी पक्ष की ओर से दावा किया गया कि दुकान में प्लास्टिक सामग्री का व्यवसाय संचालित होता था और आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी। हालांकि पुलिस जांच, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और केस डायरी में कई गंभीर तथ्य सामने आए। न्यायालय के आदेश में उल्लेख किया गया कि घटना स्थल से अधजले पटाखों के अवशेष मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया कि घनी रिहायशी गली में पटाखों और प्लास्टिक सामग्री का भंडारण किया जा रहा था। बताया गया कि घटना के समय दुकान की छत पर वेल्डिंग का कार्य चल रहा था और वेल्डिंग की चिंगारियों से आग फैलने की आशंका व्यक्त की गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के कई मकान इसकी चपेट में आ गए।

50 लाख से अधिक की क्षति,बच्ची घायल : प्रकरण में लगभग 50 से 55 लाख रुपये तक के नुकसान का उल्लेख किया गया है। घटना में एक बच्ची के घायल होने की बात भी रिकॉर्ड में दर्ज बताई गई है। आग लगने के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था और दमकल विभाग को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

न्यायालय ने मानी गंभीर लापरवाही : अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने माना कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रकृति का प्रतीत होता है। आदेश में कहा गया कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण अत्यंत खतरनाक है और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे थे। साथ ही अग्रिम जमानत मिलने की स्थिति में साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हीं आधारों पर अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।

पहले भी उठ चुकी थी आपत्ति

दस्तावेजों में यह भी उल्लेख है कि मोहल्ले के लोगों द्वारा पूर्व में भी कथित रूप से पटाखा भंडारण को लेकर आपत्ति जताई गई थी। जानकारी के अनुसार इस संबंध में पहले भी कार्रवाई की बात सामने आई है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश के बाद मामले में गंभीर धाराएं जोड़ी गईं।

शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

इस घटना ने अंबिकापुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घनी रिहायशी बस्तियों में ज्वलनशील पदार्थों के अवैध भंडारण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर अब प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी चर्चा तेज हो गई है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि शहर में ऐसे और कितने स्थान हैं जहां नियमों के विपरीत खतरनाक सामग्री रखी जा रही है, और प्रशासन इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेगा।

3 इंजेक्शन लगने के बाद भी रेबीज से वृद्ध की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 मई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रतिदिन 15 से 20 डॉग बाइट के मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया जा रहा है। इस बीच दरिमा थाना क्षेत्र में रेबीज से एक वृद्ध की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम नावापारा कला निवासी 63 वर्षीय घूरसाय को 12 मार्च को गांव के एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते ने उसके दाहिने हाथ के अंगूठे,बाएं हाथ की कुहनी और पेट में काटा था। घटना के बाद परिजन उसे इलाज के लिए नावानगर उप स्वास्थ्य केंद्र ले गए,जहां उसे पहला एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद दरिमा अस्पताल में दो और डोज दिए गए थे। परिजनों ने बताया कि चौथा इंजेक्शन 13 मई को लगना था, लेकिन इससे पहले ही 6 मई को उसकी तबीयत बिगडने़ लगी। उसे तेज बुखार, हाथ-पैर में दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे,जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

बंगाल-असम चुनाव के बाद प्रदेश सरकार पर राकेश तिवारी का तंज

'अब प्रदेश की कानून व्यवस्था और सड़कों पर भी ध्यान दीजिए,जनता रील नहीं काम देखना चाहती'

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 मई 2026
(घटती-घटना)।

राजनीतिक विश्लेषक एवं समाजसेवी Rakesh Tiwari ने पश्चिम बंगाल और असम चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी अपने बयान में कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश के मंत्री'खाना-पीना छोड़कर'प्रचंड गर्मी में प्रचार करने में जुटे रहे और उसी मेहनत का परिणाम चुनावी जीत के रूप में सामने आया। राकेश तिवारी ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि प्रदेश के कुछ मंत्रियों को असम की 14 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी,जबकि कुछ को पूरे बंगाल का दायित्व सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने'भयंकर मेहनत'कर चुनाव प्रबंधन का ऐसा प्रदर्शन किया मानो उसकी पताका पूरी सृष्टि में लहरा दी गई हो। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठाए। तिवारी ने कहा कि अब चुनाव और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था और जर्जर सड़कों की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा,जल्द ही यहां भी चुनाव होंगे और वोटर हम आम नागरिक ही होंगे। ऐसे में जनता की मूल समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जनता रीलों से उकता गई : राकेश तिवारी ने नेताओं की सोशल मीडिया सक्रियता पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता अब केवल रील और प्रचारात्मक वीडियो देखकर थक चुकी है। उन्होंने नेताओं से अपील करते हुए कहा कि यदि धरातल पर कोई वास्तविक काम हो,तभी उसे जनता के सामने लाया जाए। तिवारी ने कहा कि जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि कौन नेता क्या खा रहा है या किस शादी,छठी,बरही,मुंडन या सालगिरह समारोह में शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक अब दिखावे की राजनीति से आगे बढ़कर वास्तविक विकास कार्य और प्रशासनिक सुधार देखना चाहता है। राकेश तिवारी की यह टिप्पणी सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

एआई मानव का विकल्प नहीं, सहयोगी तकनीक : डॉ. सुशील कश्यप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 मई 2026 (घटती-घटना)।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला के चौथे दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), बायो-इन्फॉर्मेटिक्स और विधिक क्षेत्र में एआई के उपयोग पर विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सेमिनार हॉल में कुलपति प्रो. राजेन्द्र लाकपाले की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में डॉ. सुशील कश्यप,डॉ. समन नारायण उपाध्याय, डॉ. अमृता कुमारी पाण्डा तथा कंप्यूटर साइंस विभाग की छात्रा फिया ने अपना प्रस्त ने प्रस्तुतीकरण दिया। डॉ. सुशील कश्यप ने परप्लेक्सिटी,टर्निटिन जैसे शोध टूल्स की जानकारी देते हुए कहा कि आज एआई के माध्यम से डाटा विश्लेषण और शोध कार्य आसान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एआई मनुष्य का विकल्प नहीं, बल्कि सहयोगी तकनीक है, जो रचनात्मकता और कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है।

'सरगुजा के बाद अब बस्तर की बारी?' अंचल ओझा का उद्योग और खनन विस्तार पर बड़ा सवाल

'विकास के नाम पर प्रकृति,संस्कृति और आदिवासी अस्तित्व खत्म किया जा रहा',निजी कंपनियों की भूमिका पर उठाए गंभीर प्रश्न

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 मई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिक और खनन विस्तार को लेकर सामाजिक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर मुखर रहने वाले अंचल ओझा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विकास के नाम पर सरगुजा की प्रकृति, पर्यावरण और आदिवासी संस्कृति को लगातार नुकसान पहुंचाया गया और अब यही मॉडल बस्तर क्षेत्र में भी लागू करने की तैयारी चल रही है। अंचल ओझा ने कहा कि एक समय सरगुजा नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा था। जब वर्ष 2007-08 के आसपास क्षेत्र में नक्सल गतिविधियां कम हुईं, तब यह कहा गया कि अब इलाके का विकास होगा। उन्होंने माना कि कुछ विकास कार्य हुए भी, लेकिन धीरे-धीरे उसी विकास को आधार बनाकर बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और निजी कंपनियों के विस्तार का रास्ता तैयार किया गया।

'SECL के दौर और अब की स्थिति में बड़ा फर्क : उन्होंने कहा कि पहले क्षेत्र में SECL जैसी सरकारी कंपनियां काम करती थीं,जो कोयला खनन के साथ प्रभावित परिवारों को मुआवजा और रोजगार भी उपलब्ध कराती थीं। लेकिन समय के साथ सरकारी कंपनियों की भूमिका कम हुई और निजी कंपनियां क्षेत्र में सक्रिय हो गईं। ओझा का आरोप है कि निजी कंपनियां जमीन अधिग्रहण के बदले अधिक मुआवजा तो देती हैं, लेकिन पुनर्वास, स्थायी रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी के मामलों में बेहद कमजोर साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जमीन, खेत और घर गए, उनमें से कई आज भी स्थायी रोजगार और पुनर्वास के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

लाखों पेड़ कटे,अभी और कटने की तैयारी : उन्होंने दावा किया कि खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण सरगुजा क्षेत्र में लाखों पेड़ों की कटाई हो चुकी है और आने वाले समय में भी बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने की योजनाएं हैं। अंचल ओझा ने कहा कि राजस्थान जैसे राज्यों को बिजली उपलब्ध कराने के नाम पर सरगुजा की हरियाली और पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनके अनुसार निजी कंपनियां सरकार की नीतियों और संरक्षण के सहारे क्षेत्र को 'गर्म और सपाट मैदान' में बदलने की दिशा में काम कर रही हैं।

अब बस्तर में भी वही मॉडल लागू होने का खतरा : उन्होंने कहा कि अब जब सरकार बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद समाप्त होने का दावा कर रही है, उसी के साथ वहां लौह अयस्क और अन्य खनिजों के बड़े पैमाने पर दोहन की योजनाएं भी शुरू हो चुकी हैं। ओझा ने आशंका जताई कि जिस तरह सरगुजा में विकास और उद्योग के नाम पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ, वैसी ही स्थिति अब बस्तर में भी देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा, 'कभी-कभी लगता है कि नक्सलवाद से निपटना शायद आसान है, लेकिन सत्ता और शासन के संरक्षण में काम करने वाली बड़ी निजी कंपनियों से संघर्ष करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। '

'उद्योगों का विरोध नहीं,लेकिन अस्तित्व खत्म नहीं होना चाहिए ': अंचल ओझा ने स्पष्ट किया कि वे उद्योग, निजी निवेश या विकास के विरोध में नहीं हैं। उनका कहना है कि समस्या तब शुरू होती है जब विकास की कीमत आदिवासी समाज, स्थानीय संस्कृति,जंगल,जल और पर्यावरण को चुकानी पड़े। उन्होंने कहा कि यदि विकास के नाम पर आदिवासी पहचान,लोकसंस्कृति,वन्यजीव और पर्यावरण को खत्म किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से विरोध और संघर्ष भी सामने आएंगे।

आदिवासी नेतृत्व और सरकार की नीतियों पर सवाल : ओझा ने प्रदेश की वर्तमान सरकार और आदिवासी नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद हसदेव क्षेत्र, रायगढ़ और अब बस्तर में बड़ी कंपनियों के विस्तार से यह सवाल उठता है कि सरकार आदिवासी संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर देश और राज्य की कई बड़ी कंपनियां सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में निवेश की तैयारी कर रही हैं। अंचल ओझा की यह टिप्पणी क्षेत्र में चल रही खनन परियोजनाओं, औद्योगिक विस्तार और पर्यावरणीय मुद्दों पर जारी बहस को एक बार फिर केंद्र में ले आई है।

बस्तर में लगेंगे ये बड़े उद्योग :

- दंतेवाड़ा - आर्सेलर मित्तल निपॉन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड,गुजरात - स्टील
- जगदलपुर - मां दुर्गा आयरन एंड स्टील प्रायवेट लिमिटेड,दिल्ली - स्टील
- दंतेवाड़ा - हाला मोबेलिटी प्रायवेट इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद - इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल
- जगदलपुर - ग्रीन टेक सोल्यूशन,हैदराबाद - स्टील
- कांकेर - बृजधाम इस्पात प्रायवेट लिमिटेड - ऊर्जा
- कांकेर - शंकरा लेटेक्स इंडस्ट्री - फार्मा

ये नए बड़े उद्योग यहां लगेंगे :

- अडानी पॉवर लिमिटेड - छत्तीसगढ़ राज्य - ऊर्जा
- अडानी इंटरप्रायजेज गुजरात - सरगुजा - केमिकल
- जिंदल पॉवर - रायगढ़ - ऊर्जा
- जिंदल पॉवर - तमनार रायगढ़ - ऊर्जा
- जिंदल पॉवर - रायगढ़ - ऊर्जा
- गेल इंडिया लिमिटेड - राजनांदगांव - फर्टीलाइजर
- जेके लक्ष्मी सीमेंट - दुर्ग - सीमेंट
- टीवी पॉवर - सक्ती - ऊर्जा
- टोरेंट पॉवर गुजरात - रायगढ़ - ऊर्जा
- रूंगटा सन्स कोलकाता - रायगढ़ - स्टील
- बजरंग पॉवर एंड इस्पात - बेमेतरा - ऊर्जा
- हिंदुजा एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड - बिलासपुर - ऊर्जा

सरगुजा संभाग में महिला नेतृत्व की बड़ी दस्तक...6 में से 4 जिलों की कमान महिला कलेक्टरों के हाथ,शासन की तबादला सूची ने बदले प्रशासनिक समीकरण

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल,7 में से 5 जिलों की कमान महिला आईएएस अधिकारियों को,सरगुजा संभाग सबसे ज्यादा चर्चा में...

सरगुजा संभाग में महिला शक्ति का उदय,6 में से 4 जिलों की कमान महिला कलेक्टरों के हाथ

प्रशासनिक फेरबदल में सरगुजा संभाग के चार जिलों में बदले कलेक्टर... बलरामपुर,कोरिया,एमसीबी और सूरजपुर को मिली महिला कलेक्टर

43 अफसरों की तबादला सूची में सरगुजा सबसे ज्यादा चर्चा में, चार जिलों में महिला नेतृत्व

-न्यूज डेस्क-

बैकुंठपुर,07 मई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची ने प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल को अचानक तेज कर दिया है,43 वरिष्ठ अधिकारियों के नामों वाली इस सूची में कई विभागों में बदलाव किए गए,लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिला कलेक्टरों की नई पदस्थापनाओं को लेकर हो रही है,वजह भी साफ है जिन सात जिलों में कलेक्टर बदले गए, उनमें से पांच जिलों की कमान महिला आईएएस अधिकारियों को सौंप दी गई है, यह सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे शासन के भीतर बदलते प्रशासनिक संतुलन,महिला नेतृत्व को बढ़ावा और नई कार्यशैली की ओर संकेत के रूप में देखा जा रहा है,खासकर सरगुजा संभाग में हुए बदलावों ने नौकरशाही से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

सरगुजा संभाग बना चर्चा का केंद्र

पूरे तबादला आदेश में सबसे ज्यादा नजरें सरगुजा संभाग पर टिकी हुई हैं,छह जिलों वाले इस संभाग में चार जिलों की कमान अब महिला कलेक्टरों के हाथों में होगी, नई नियुक्तियों के अनुसार–बलरामपुर-रामानुजगंज – चंदन संजय त्रिपाठी, कोरिया – पुष्पा साहू, एमसीबी – संतान देवी जांगड़े, सूरजपुर – रेना जमील,इन चार जिलों में महिला आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलकों में अलग-अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरगुजा संभाग जैसे बड़े आदिवासी और संवेदनशील क्षेत्र में महिला नेतृत्व इतनी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है।

43 नामों की सूची,लेकिन फोकस सिर्फ कलेक्टरों पर...

हालांकि तबादला सूची में सचिव स्तर से लेकर विभागीय प्रमुखों तक कुल 43 अधिकारियों के नाम शामिल हैं, लेकिन लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी जिला कलेक्टरों के बदलाव में ही दिखाई दे रही है, इसका बड़ा कारण यह है कि जिला कलेक्टर किसी भी जिले में शासन का सबसे अहम चेहरा माने जाते हैं,योजनाओं का क्रियान्वयन,कानून व्यवस्था,राजनीतिक समन्वय और जनता से सीधा संपर्क—सब कुछ काफी हद तक कलेक्टर की कार्यशैली पर निर्भर करता है,ऐसे में किसी जिले में कलेक्टर बदलना सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं,बल्कि पूरे जिले के प्रशासनिक माहौल में बदलाव माना जाता है।

महिला नेतृत्व को बड़ा संदेश

सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है,पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी के जरिए बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और अब उन्हें सिर्फ दफ्तरों तक सीमित न रखकर फील्ड में बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं,प्रशासनिक जानकार मानते हैं कि महिला अधिकारी आमतौर पर जनसुनवाई, सामाजिक योजनाओं की निगरानी,शिक्षा,स्वास्थ्य और महिला-बाल विकास जैसे मुद्दों पर अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ काम करती हैं,यही कारण है कि सरकार अब उन्हें महत्वपूर्ण जिलों की कमान देने में पीछे नहीं हट रही।

सबसे ज्यादा चर्चा चंदन त्रिपाठी को लेकर...

इस पूरी तबादला सूची में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक नाम को लेकर हो रही है,तो वह है चंदन संजय त्रिपाठी,कोरिया जिले की कलेक्टर रहीं चंदन त्रिपाठी को अब बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, सामान्य तौर पर इस बार जिन कलेक्टर को हटाया गया सभी को सचिवालय या किसी विभागीय जिम्मेदारी में भेज दिया गया है, सरगुजा संभाग में जिन अन्य कलेक्टरों को हटाया गया उनमें अधिकांश को दोबारा जिला नहीं मिला, ऐसे में यह सवाल प्रशासनिक गलियारों में तेजी से उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या रहा कि चंदन त्रिपाठी को उसी सरगुजा संभाग फिर से जिले की कमान पाने में सफल रहीं?

सरगुजा संभाग में महिला नेतृत्व की बड़ी दस्तक

6 में से 4 जिलों की कमान महिला कलेक्टरों के हाथ

रेन्ना जमील	चंदन संजय त्रिपाठी	पुष्पा साहू	संतान देवी जांगड़े
नई कलेक्टर, सूरजपुर (2019 बैच)	कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज (IAS)	कलेक्टर, कोरिया (IAS)	कलेक्टर, एमसीबी (IAS)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी 43 अधिकारियों की तबादला सूची में सरगुजा संभाग के चार जिलों के कलेक्टर बदले

- सरगुजा संभाग के 6 जिले: सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, एमसीबी, जशपुर, सरगुजा
- 4 जिलों में महिला कलेक्टरों की नियुक्ति से संभाग में प्रशासन को मिलेगी नई दिशा

'पहुंच' और 'मैनेजमेंट' पर उठ रहे सवाल

तबादला सूची सामने आने के बाद नौकरशाही के भीतर सबसे ज्यादा चर्चाएं 'मैनेजमेंट' और 'पहुंच' को लेकर हो रही हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या चंदन त्रिपाठी की प्रशासनिक कार्यशैली इतनी प्रभावशाली रही कि शासन ने उन्हें दोबारा जिला सौंपना उचित समझा? या फिर इसके पीछे उनका मजबूत प्रशासनिक नेटवर्क और सत्ता स्तर तक बेहतर समन्वय रहा? हालांकि आधिकारिक तौर पर शासन हर तबादले को प्रशासनिक जरूरत और प्रदर्शन के आधार पर ही बताता है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस फैसले को लेकर कई तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं, कुछ अधिकारी इसे उनकी बेहतर कार्यकुशलता और संभाग में अनुभव का परिणाम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे 'मजबूत पकड़' और 'बेहतर समन्वय' का असर मान रहे हैं।

कोरिया और एमसीबी में परिचित चेहरे

कोरिया जिले में पुष्पा साहू की नियुक्ति को 'अनुभव आधारित पोस्टिंग' माना जा रहा है, वे पहले भी कोरिया जिला पंचायत की सीईओ रह चुकी हैं और क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था से परिचित हैं, वहीं, एमसीबी जिले में संतान देवी जांगड़े की नियुक्ति भी चर्चा में है, वे भी पूर्व में कोरिया जिला पंचायत सीईओ रह चुकी हैं, ऐसे में शासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि क्षेत्रीय अनुभव रखने वाले अधिकारियों पर भरोसा किया जा रहा है।

सूरजपुर में रेना जमील की एंट्री

सूरजपुर जिले में रेना जमील की नियुक्ति को लेकर भी प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं, सूरजपुर जिला संवेदनशील माना जाता है और यहां प्रशासनिक सक्रियता हमेशा महत्वपूर्ण रहती है, ऐसे में नए कलेक्टर के रूप में उनकी कार्यशैली पर सबकी नजर रहेगी।

क्या बदलेंगे प्रशासनिक समीकरण?

सरगुजा संभाग में हुए इस बड़े फेरबदल ने कई पुराने प्रशासनिक समीकरण बदल दिए हैं,अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नई महिला कलेक्टरों की टीम किस तरह काम करती है और क्या वास्तव में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई बड़ा बदलाव दिखाई देता है,फिलहाल इतना तय है कि इस तबादला सूची ने छत्तीसगढ़ की नौकरशाही में नई बहस छेड़ दी है क्या यह सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल है,या फिर शासन की नई रणनीति की शुरुआत?

क्या बदलेंगे जिलों के हालात?

सरगुजा संभाग के जिन जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति हुई है,वहां कई चुनौतियां पहले से मौजूद हैं, कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों में है, कहीं शिक्षा व्यवस्था, तो कहीं राजस्व और ग्रामीण विकास के मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं, ऐसे में नए प्रशासनिक नेतृत्व से लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, अब देखना होगा कि नए कलेक्टर अपने-अपने जिलों में किस तरह की प्रशासनिक प्राथमिकताएं तय करते हैं और जनता को कितना राहत दिला पाते हैं, फिलहाल इतना तय है कि छत्तीसगढ़ शासन की इस तबादला सूची ने सरगुजा संभाग के प्रशासनिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं और आने वाले दिनों में इसका असर जमीनी प्रशासन पर भी दिखाई देगा।

महिला आरक्षण पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला

कांग्रेस बोली- शुरू से महिला आरक्षण के समर्थन में रही पार्टी, भाजपा फैला रही भ्रम

-संवाददाता-

बलरामपुर,07 मई 2026 (घटती-घटना)। महिला आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण की समर्थक रही है,जबकि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीतिक भ्रम फैलाकर श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में कहा गया कि भाजपा लगातार यह प्रचारित कर रही है कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन नहीं किया, जिसके कारण संसद में यह कानून लंबे समय तक पारित नहीं हो सका। कांग्रेस ने इस दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है और संसद से लेकर पंचायत स्तर तक महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए काम किया है।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही बन चुका कानून' : कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा द्वारा लाया गया 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' संसद से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कर चुका है और अब वह कानून का रूप ले चुका है। इसके बावजूद भाजपा महिला आरक्षण लागू करने में देरी कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा

अब परिशीमन को आधार बनाकर महिला आरक्षण लागू करने को टालना चाहती है। पार्टी का कहना है कि यदि सरकार की मंशा साफ होती तो वर्तमान सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू किया जा सकता था।

परिशीमन के मुद्दे पर उठाए सवाल : कांग्रेस ने कहा कि 16 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत 131वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से भाजपा लोकसभा सीटों के परिशीमन की दिशा में आगे बढ़ना चाहती थी। प्रस्तावित संशोधन में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 850 करने का प्रावधान बताया गया था, जिसमें 815 सीटें राज्यों तथा 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित थीं। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि परिशीमन के लिए वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार स्वयं 2026-27 में नई जनगणना कराने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में पुराने आंकड़ों के आधार पर परिशीमन का औचित्य समझ से परे है।

'सरकार चाहती तो तुरंत लागू हो सकता था आरक्षण : कांग्रेस ने कहा कि यदि भाजपा वास्तव में महिलाओं को तत्काल राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहती, तो 2023 में पारित कानून में संशोधन कर वर्तमान सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू किया जा सकता था। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर प्रक्रिया को लंबा खींच रही है ताकि महिला आरक्षण के मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाया जा सके।

पंचायत और नगरीय निकायों में आरक्षण का श्रेय कांग्रेस को : कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिलाने का ऐतिहासिक कार्य भी कांग्रेस सरकारों के दौरान हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री Rajiv Gandhi और P. V. Narasimha Rao के प्रयासों से पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया गया था।

सभी न्यायालयों मे नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मई को

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,07 मई 2026 (घटती-घटना)। राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार मान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर) (छ.ग.) श्री शक्ति सिंह राजपूत जी के मार्गदर्शन में आगामी दिनांक 09/05/2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा (अम्बिकापुर) (छ.ग.) के अंतर्गत सभी न्यायालयों, मे नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, व्यवहार प्रकरण,चैक बाउंस प्रकरण,परिवारिक विवाद, दुर्घटना संबंधी दावा,मजदूरों सं संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, राजस्व प्रकरण, विद्युत चोरी संबंधी प्रकरण जैसे प्री-लिटीगेशन के प्रकरणों का भी निराकरण आपसी सहमति के माध्यम से किया जा सकता है। मान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर) (छ.ग.) श्री शक्ति सिंह राजपूत जी द्वारा व्यक्त किया गया कि हाईब्रिड लोक अदालत के माध्यम से पुनः पक्षकारगण को यह अवसर प्रदान हो रहा कि वे राजीनामा योग्य प्रकरणों में अपनी आपसी सहमति के आधार पर अपने मध्य के विवाद का अंत कर सकते हैं।

पक्षकार मामले का निराकरण आपसी सहमति से करने हेतु संबंधित न्यायालय, जहां उनका प्रकरण लंबित है, के समक्ष व्यक्तिगत रूप से होने के अलावा वर्चुअल कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से भी उपस्थित हो सकते हैं और इस प्रकार न्यायालय में आये बिना भी अपने मामले का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर करा सकते हैं। मान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर) (छ.ग.) श्री शक्ति सिंह राजपूत जी द्वारा आमजनों से अपील किया गया है कि दिनांक 09/05/2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा (अम्बिकापुर) (छ.ग.) के अंतर्गत सभी न्यायालयों तथा व्यवहार न्यायालय सीतापुर सरगुजा (छ.ग.) में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से अपने अपने विवाद का निराकरण करा कर अपने मध्य के मतभेदों को समाप्त करने के इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठावें तथा नेशनल लोक अदालत के सफल कियांवयन में सहयोग प्रदान करें।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका शमीमा बेगम पति कलिमुल्ला कुरैशी, उम्र- 60 वर्ष जाति-कसाब निवासी वार्ड नं. 35 मायापुर, अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदिका के द्वारा अनावेदक मो. मुस्तफा पिता अब्दुल अजीत मिया, उम्र 68 वर्ष, जाति मंसूरी निवासी अजीज हाउस नं. 45 हफीजुला अंसारी गली, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर शीट न0 03, मोहल्ला कौवाड़ांड़ स्थित नजूल भूमि प्लाट नंबर 1541 कुल रकबा 0.05 एकड़ में से रकबा 1113.25 वर्गफीट भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2026 के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर क्रयशुदा उक्त भूमि के नजूल अभिलेख में स्वयं का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदिका द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक - 25/05/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक-05/05/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर,सरगुजा

ईश्तेहार/सूचना

मै प्रेमचन्द्र तायल पिता स्व0 राम कुमार तायल उम्र लगभग 62 वर्ष निवासी बी एस 04 कुण्डला वसुधरा सिटी ,अम्बिकापुर,छ0ग0।
यह कि मेरे द्वारा स्टेट बैंक आफ इडिया शाखा विश्रामपुर में मेरे पुत्री के नाम पर 05 बॉण्ड लिया गया था जिसमे मेरी पुत्री का पहले का नाम NIKKEY AGRAWAL अंकित है।
यह मेरे पुत्री के आधार कार्ड एवं पेन कार्ड मे मेरे पुत्री का नाम RADHA TAYALअंकित है
यह उक्त दोनो नाम NIKKEY AGRAWAL एवं RADHA TAYAL उक्त दोनो नाम मेरे पुत्री का ही नाम है मै अपने पुत्री के नाम के शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय में काम आवे।

सपथकर्ता
प्रेमचन्द्र तायल
निवासी बी एस 04 कुण्डला वसुधरा सिटी ,अम्बिकापुर,छ0ग0

ईश्तेहार/सूचना

सुचित किया जाता है कि हमारे फर्म मेसर्स माँ अम्बा कंस्ट्रक्शन रजि0 ऑफिस- बाबूपारा, अम्बिकापुर तह0 अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 से आज दिनांक 07.05.2026 से भागीदार (1) श्री बालमुकुन्द वर्मा आ0 श्री विश्वनाथ वर्मा निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर (2) श्री बृज कुमार सिंह आ0 श्री दीप नारायण सिंह निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर तह0 अम्बिकापुर (3) श्री देव नारायण यादव आ0 श्री रामजग यादव निवासी जेल रोड़ बाबूपारा अम्बिकापुर (4) श्री निलेश चतुर्वेदी आ0 श्री शिव राम चतुर्वेदी निवासी रावत रेसीडेंसी एम. जी. रोड़ अम्बिकापुर अलग (रिटायर) हो गये हैं, उक्त फर्म में अब इनका कोई लेना देना नहीं है एवं श्री सशक्त रघुवंशी आ0 श्री अतुल सिंह निवासी बाबूपारा अम्बिकापुर नये पार्टनर के रूप में आज दिनांक 07.05.2026 से शामिल हो गये हैं।

सूचनार्थ

M/s Maa Amba Construction
Atul Singh
Partner

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0 /20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शंकर राय आ0 बैधनाथ राय जाति भूमिहार (ब्राम्हण), निवासी केदारपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-केदारपुर, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 47 / 50 रकबा 0.06 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो, अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 14/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 17/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0 /20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सुशीला देवी आ0 प्रयाग राज अगवाल जाति निवासी दर्रीपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला अस्पताल रोड, शीट नम्बर-10 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 4211 रकवा 0.04 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो, अपना लिखित दावा/ आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 14/5/20260 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 17/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0 /20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रूवी जैन आ0/पति अजीत जैन जाति, निवासी चोपड़ापारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-चोपड़ापारा, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 9/153 रकबा 0.03 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 08/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 23/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,(छ0ग0)

रा0प्र0क्र0 /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिवशंकर अग्रवाल आ0स्व0अशोक कुमार अग्रवाल निवासी वार्ड नंबर 09 जवाहर मार्केट महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड अम्बेडकर चौक अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 2/939 रकबा 0.020 हे0 भूमि को अनावेदक अरूण कुमार आ0 धनेश्वर प्रसाद व अन्य निवासी मंदिरपारा ग्राम बन्दना पो0कोट तहसील सीतापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास अपने निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि रूपये 7,50,000/- में भूमि बिक्री करने का सौदा तय कर बिकी अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 20.05.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दिवा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।आज दिनांक- 04/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील

तहसीलदार
,अंबिकापुर,सरगुजा

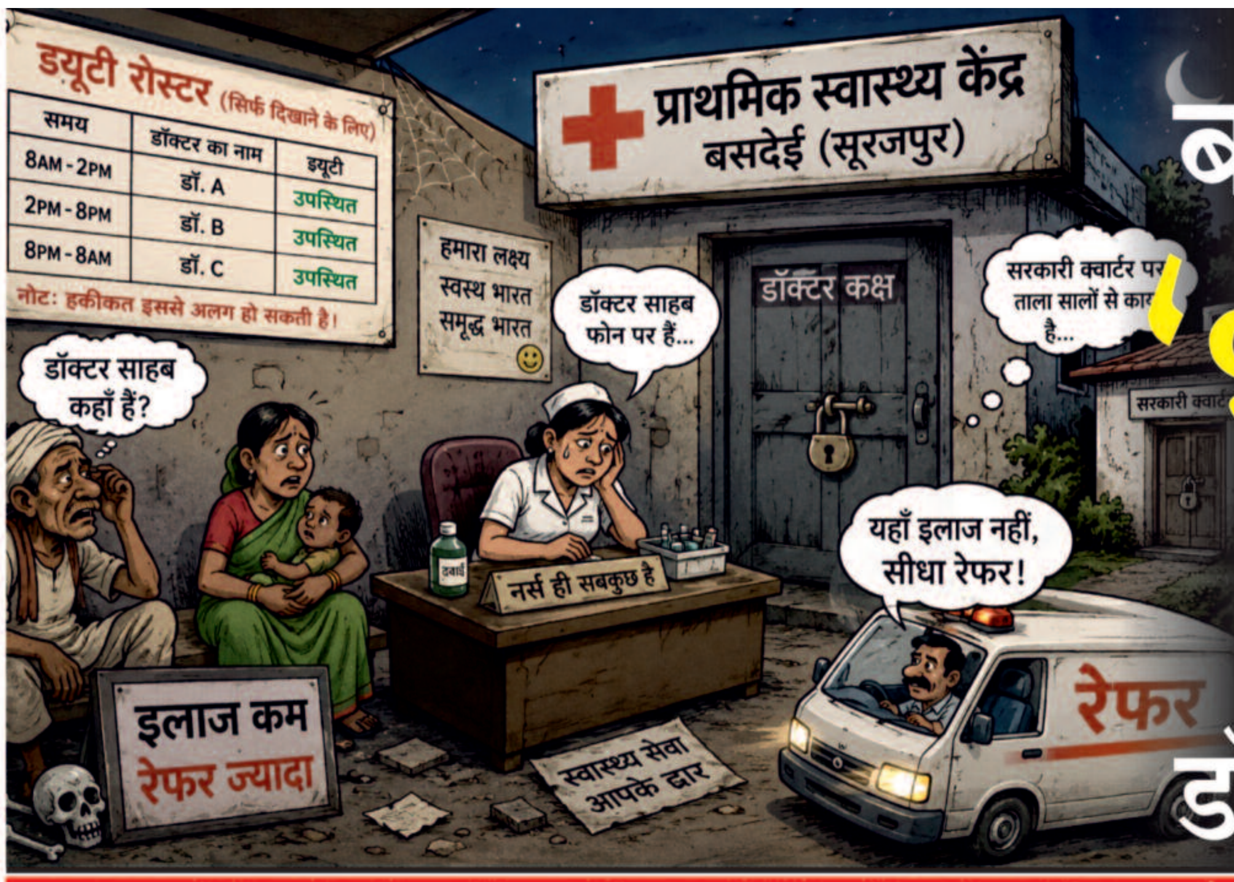

बसदेई PHC की रातें 'भगवान भरोसे'

....ड्यूटी रोस्टर दीवार पर, डॉक्टर नदारद और मरीज रेफर

कागजों में ड्यूटी,हकीकत में गायब डॉक्टर,बसदेई पीएचसी बना रेफर सेंटर

सरकारी क्वार्टर पर ताला,अस्पताल में हाहाकार,बसदेई पीएचसी की बदहाल व्यवस्था

नाइट ड्यूटी सिर्फ फाइलों में! बसदेई पीएचसी में नर्स के भरोसे मरीजों की जिंदगी

बसदेई पीएचसी में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल,डॉक्टर घर पर,मरीज रेफर पर

रोस्टर बना दिखावे का साधन? बसदेई पीएचसी में रात को नहीं मिलते डॉक्टर

मुख्यालय से गायब प्रभारी,इलाज से गायब भरोसा, बसदेई पीएचसी पर उठे सवाल

डॉक्टर नदारद, रेफर जारी,बसदेई PHC की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल

दीवार पर ड्यूटी चार्ट,अस्पताल में खाली कुर्सियां,बसदेई क्वार्ष्ट की सच्चाई

-शमरोज खान-

सूरजपुर,07 मई 2026 (घटती-घटना)। सूरजपुर जिले के बसदेई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों गंभीर सवालों के घेरे में है,कागजों में अस्पताल में डॉक्टरों की ड्यूटी तय है,नाइट रोस्टर भी बना हुआ है,लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है,रात होते ही अस्पताल की व्यवस्था लगभग नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चलने लगती है और मरीजों को इलाज से ज्यादा रेफर मिलने की उम्मीद रहती है, ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी तो लगाई जाती है,लेकिन अधिकांश समय डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं रहते,ऐसे में इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का प्राथमिक उपचार नर्सों के भरोसे होता है और गंभीर हालत होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय सूरजपुर रेफर कर दिया जाता है, सवाल यह उठ रहा है कि जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही डॉक्टर उपलब्ध नहीं होंगे,तो ग्रामीण क्षेत्र के मरीज आखिर जाएं तो जाएं कहां?

ड्यूटी रोस्टर सिर्फ दीवार की शोभा?

बसदेई पीएचसी में डॉक्टरों के लिए बाकायदा ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया है, रोस्टर में किस डॉक्टर की कब ड्यूटी है, यह स्पष्ट रूप से दर्ज है,लेकिन स्थानीय लोगों और सूत्रों का कहना है कि यह रोस्टर सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है, ग्रामीणों के मुताबिक,रोस्टर में नाम जरूर लिखा रहता है,लेकिन ड्यूटी के समय डॉक्टर नजर नहीं आते, अस्पताल की दीवारों पर चस्पा ड्यूटी चार्ट और अस्पताल की वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर दिखाई देता है,आरोप है कि यह व्यवस्था केवल निरीक्षण और कागजी खानापूर्ति तक सीमित होकर रह गई है।

नियम क्या कहते हैं?

ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ डॉक्टरों के लिए मुख्यालय में निवास करना इसलिए अनिवार्य माना जाता है ताकि इमरजेंसी के समय तुरंत सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उद्देश्य ही ग्रामीण मरीजों को तत्काल और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा देना है, लेकिन बसदेई पीएचसी की स्थिति यह सवाल खड़ा कर रही है कि यदि डॉक्टर मुख्यालय में मौजूद ही नहीं रहेंगे,तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य कैसे पूरा होगा?

जिम्मेदार मौन क्यों ?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, लोगों का कहना है कि निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं कागजों में दुरुस्त दिखाई जाती हैं, जबकि जमीनी सच्चाई अलग होती है।

अब सवाल यह उठता है कि...

क्या ड्यूटी रोस्टर सिर्फ दिखावे के लिए बनाया जा रहा है?

आखिर नाइट ड्यूटी में डॉक्टर अस्पताल में मौजूद क्यों नहीं रहते?

सरकारी क्वाटर खाली होने के बावजूद मुख्यालय में निवास क्यों नहीं किया जा रहा?

क्या स्वास्थ्य विभाग इस लापरवाही पर कार्रवाई करेगा?

या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?

रात में डॉक्टर नहीं,फोन पर चलती व्यवस्था

सूत्रों के अनुसार,नाइट ड्यूटी के दौरान कई बार डॉक्टर अस्पताल में उपस्थित नहीं रहते और स्थिति की जानकारी फोन पर ली जाती है, ऐसे में किसी गंभीर मरीज के आने पर नर्सिंग स्टाफ को ही स्थिति संभालनी पड़ती है,हालांकि नर्सिंग स्टाफ अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है,लेकिन बिना डॉक्टर के गंभीर मरीजों का उपचार करना जोखिम भरा साबित हो सकता है,कई बार सही निर्णय लेने में देरी मरीज की हालत को और बिगाड़ सकती है।

इलाज कम,रेफर ज्यादा

बसदेई पीएचसी को लेकर ग्रामीणों में सबसे बड़ी नाराजगी यही है कि यहां इलाज से ज्यादा रेफर किया जाता है, हल्की गंभीर स्थिति वाले मरीजों को भी जिला अस्पताल सूरजपुर भेज दिया जाता है,इससे मरीजों और उनके परिजनों को अतिरिक्त आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है, रात के समय स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण तत्काल वाहन की व्यवस्था करना आसान नहीं होता। कई बार मरीज घंटों तक अस्पताल परिसर में इंतजार करते रहते हैं।

प्रभारी डॉक्टर पर भी उठे सवाल

बसदेई पीएचसी की प्रभारी डॉक्टर पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, आरोप है कि वे मुख्यालय में निवास नहीं करतीं और रोजाना अपने निजी निवास से आना-जाना करती हैं,सबसे बड़ा सवाल उस सरकारी क्वार्टर को लेकर है जो उनके लिए आवंटित किया गया है, स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर में बना सरकारी आवास वर्षों से बंद पड़ा है और उस पर ताला लटका हुआ है,ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रभारी डॉक्टर मुख्यालय में ही निवास करें,तो आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तुरंत उपचार मिल सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में रात के समय मरीजों को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल पा रही।

ग्रामीणों में बढ़ रहा आक्रोश

स्वास्थ्य सेवाओं की इस स्थिति को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, लोगों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टरों की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित होनी चाहिए और नाइट ड्यूटी की वास्तविक मॉनिटरिंग की जानी चाहिए,ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की यही स्थिति रही, तो सरकार की ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाएंगी।

बड़ा सवाल अब भी कायम

बसदेई पीएचसी की मौजूदा स्थिति सिर्फ एक अस्पताल की समस्या नहीं,बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की उस तस्वीर को सामने ला रही है जहां कागजों में व्यवस्था दुरुस्त दिखती है,लेकिन जमीन पर मरीज अब भी भगवान भरोसे हैं।

सोनहत के आसमान में मंडराता रहस्य : कम ऊंचाई पर उड़ते चार्टर्ड प्लेन ने बढ़ाई धड़कनें,चर्चाओं का बाजार गर्म

-संवाददाता-

सोनहत (कोरिया),07 मई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र सोनहत में पिछले कुछ दिनों से आसमान में एक छोटा चार्टर्ड प्लेन कौतूहल का विषय बना हुआ है, यह विमान क्षेत्र के ऊपर काफी कम ऊंचाई पर लगातार चक्कर लगा रहा है,जिसे लेकर ग्रामीणों और स्थानीय बुद्धिजीवियों के बीच तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे इस शांत इलाके में अचानक शुरू हुई इस हवाई गतिविधि ने लोगों के बीच बेचैनी और उत्सुकता दोनों पैदा कर दी है।

ग्रामीण इलाकों में चर्चा है कि यह विमान किसी बड़ी निजी कंपनी, संभवतः अडानी अथवा अन्य ग्रुप के किसी आगामी प्रोजेक्ट से संबंधित सर्वे के लिए भेजा गया है। लोग इसे नए कोयला ब्लॉक या खनिज संपदा की खोज से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं,एक पक्ष का मानना है कि यह केंद्र या राज्य सरकार की किसी विशेष योजना (जैसे डिजिटल लैंड सर्वे या वन संरक्षण) के लिए किया जा रहा हवाई सर्वेक्षण हो सकता है। फिलहाल, प्रशासनिक स्तर पर इस विमान की पहचान और इसके उद्देश्य को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जिससे कयासों का दौर जारी है।

आखिर क्या हो सकता है यह विमान?

कुछ जानकारों से बात करने पर उन्हनो सम्भावना जाहिर करते हुए कहा कि सोनहत जैसे भूगर्भीय रूप से समृद्ध और संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि के पीछे खनिज सर्वेक्षण से सम्बंधित कुछ हो सकता है।

एरोमैग्नेटिक खनिज सर्वेक्षण

कोरिया जिला खनिज संसाधनों से भरपूर है, अक्सर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या निजी कंपनियां जमीन के भीतर दबे कोयले या अन्य कीमती खनिजों का पता लगाने के लिए यह सर्वे करती हैं, विमान का कम ऊंचाई पर बार-बार घूमना इस बात का संकेत देता है कि वह किसी विशेष ग्रिड या पैटर्न के आधार पर डेटा एकत्र कर रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी सौगात

जशपुर में श्री नदी पर बनेगा उच्च स्तरीय पुल

9 करोड़ 45 लाख की लागत से होगा निर्माण,छत्तीसगढ़-झारखंड-ओडिशा की कनेक्टिविटी होगी मजबूत

-संवाददाता-

रायपुर,07 मई 2026 (घटती-घटना)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले को एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना की सौगात मिली है। राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के बजट अंतर्गत कुनकुरी-तपकरा-लवाकेरा मार्ग पर श्री नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए 9 करोड़ 45 लाख 85 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

यह सड़क मार्ग छत्तीसगढ़,झारखंड और ओडिशा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग माना जाता है। उच्च स्तरीय पुल के निर्माण से तीनों राज्यों के बीच आवागमन अधिक सुरक्षित, सुगम और निर्बाध हो सकेगा। साथ ही व्यापार,परिवहन,शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

वर्तमान में इस मार्ग पर स्थित सकरा पुल बरसात के मौसम में लोगों के लिए बड़ी समस्या बन जाता था। श्री नदी में जलस्तर बढ़ने पर आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो जाता था, जिससे ग्रामीणों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार लोगों को जोखिम उठाकर नदी पार करनी पड़ती थी। क्षेत्रवासी लंबे समय से यहां उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। अब प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

क्षेत्रवासियों ने जताया आभार

स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण से हजारों लोगों को सुरक्षित और बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा प्राप्त होगी।

विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा पुल

क्षेत्रवासियों का मानना है कि श्री नदी पर बनने वाला यह उच्च स्तरीय पुल जशपुर जिले के लिए विकास का नया द्वार साबित होगा। इससे दूरस्थ अंचलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना न केवल परिवहन सुविधा को मजबूत करेगी, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कोरिया से गईं कलेक्टर,अब चुगली गैंग का क्या होगा?

कलेक्ट्रेट में छाई बेचैनी!

कलेक्टर बदलीं तो मायूस हुआ 'सिपहसालार' नेटवर्क! कोरिया कलेक्ट्रेट में चर्चाओं का दौर

अभियान, पुरस्कार और छबि की राजनीति

- "आवा पानी झोंकी" अभियान चर्चा में रहा
- पीएम मोदी की "मन की बात" में हुआ था जिक्र
- प्रचार ज्यादा, परिणाम कम ?

पुरस्कारों वाला प्रशासन या दिखावे की सरकार?

- कई पुरस्कार और प्रशंसा मिली
- मूलभूत समस्याएं अब भी जस की तस
- क्या सिर्फ चमक के लिए थे अभियान ?

कलेक्टर बदलीं, अब बदलेंगे समीकरण?

- "सिपहसालारों" के चेहरे पर मायूसी
- इनर सर्किल की धड़कनें बढ़ीं
- नई कलेक्टर से उम्मीदें भी कई

राहुल वेकंट मंत्रालय भेजे गए, चर्चा फिर तेज

- ईमानदार छबि के अधिकारी माने जाते थे
- जिले की जिम्मेदारी न देकर मंत्रालय भेजा गया
- सिस्टम में तुलना और चर्चाएं तेज

पुरस्कार ज्यादा, लेकिन समस्याएं भी बरकरार?

चंदन त्रिपाठी के कार्यकाल में जिले को कई पुरस्कार,प्रशंसा और प्रशासनिक उपलब्धियां मिलीं। लेकिन अब उनके जाने के बाद विरोधी खेमे से यह आवाज भी उठने लगी है कि क्या ये उपलब्धियां स्थायी बदलाव में बदल पाईं?

क्या कहते हैं आलोचक

- स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी बदहाल है
- ग्रामीण सड़कें कई जगह खराब हैं
- राजस्व विवादों का ढेर लगा है
- पेयजल संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ
- कई योजनाएं कागजों और आयोजनों तक सीमित रहीं ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि सब कुछ इतना सफल था, तो जनता की मूल समस्याएं लगातार क्यों बनी रहीं?

कोरिया कलेक्ट्रेट का 'इनर सर्किल' संकट में,चंदन त्रिपाठी के तबादले के बाद बढ़ी धड़कनें

कोरिया से बलरामपुर पहुंचीं चंदन त्रिपाठी, पीछे छोड़ गईं चर्चाओं का लंबा दौर

कोरिया में पुरस्कारों वाला प्रशासन या दिखावे की सरकार? तबादले के बाद उठे सवाल

अभियान, पुरस्कार और छवि की राजनीति, अब बलरामपुर में होगा नया अध्याय

काम कम, चमक ज्यादा? तबादले के बाद फिर चर्चा में कोरिया कलेक्टर का कार्यकाल

कलेक्टर बदलीं, अब बदलेंगे समीकरण? कोरिया कलेक्ट्रेट की लॉबी में छाई बेचैनी

कलेक्टर चली गईं, लेकिन सवाल बाकी, क्या खत्म होगा कलेक्ट्रेट का संगठित गिरोह?

कलेक्ट्रेट में चलता था समानांतर प्रशासन? तबादले के बाद खुलकर होने लगी चर्चा

कोरिया से बलरामपुर रवाना हुईं कलेक्टर चंदन त्रिपाठी,लेकिन सिपहसालारों का क्या होगा?

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,07 मई 2026 (घटती-घटना)। राज्य शासन द्वारा जारी बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद कोरिया जिले की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है,कोरिया कलेक्टर रहीं चंदन संजय त्रिपाठी को अब बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, आदेश जारी होते ही जहां एक ओर औपचारिक बधाइयों का दौर शुरू हुआ, वहीं दूसरी ओर कोरिया कलेक्ट्रेट के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी, खामोशी और हलचल भी देखने को मिलने लगी,कलेक्ट्रेट के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा उन लोगों को लेकर हो रही है जिन्हें पिछले कुछ वर्षों से कलेक्टर के खास, इनर सर्किल, सिपहसालार नेटवर्क या फिर व्यंग्य में चुगली ब्रिगेड कहा जाता रहा। अब जब कलेक्टर बदल गई हैं, तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस कथित नेटवर्क का भविष्य क्या होगा? क्या नई कलेक्टर के आने के बाद प्रशासनिक समीकरण बदलेंगे या फिर वही पुराना ढांचा नए चेहरे के साथ काम करता रहेगा?

कोरिया में अब क्या बदलेगा?

कोरिया जिले में अब नए कलेक्टर के रूप में पुष्पा साहू की एंट्री हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कलेक्ट्रेट की प्रशासनिक संस्कृति बदलेगी? क्या चुगली ब्रिगेड का असर खत्म होगा? क्या स्टेनो लॉबी कमजोर पड़ेगी? क्या नई कलेक्टर पूरी तरह नई टीम बनाएंगी? या फिर पुरानी व्यवस्था ही नए चेहरे के साथ चलती रहेगी? फिलहाल कलेक्ट्रेट के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर है।

उपलब्धियों और आरोपों के बीच खत्म हुआ कार्यकाल

कोरिया कलेक्टर के रूप में चंदन संजय त्रिपाठी का कार्यकाल उपलब्धियों,पुरस्कारों, अभियानों और विवादों—सभी का मिश्रण रहा,समर्थकों के लिए यह ऊर्जावान और चर्चित प्रशासनिक कार्यकाल था,जबकि आलोचकों के लिए यह छवि आधारित प्रशासन का दौर रहा, अब जब वे बलरामपुर जा चुकी हैं,तो कोरिया में सिर्फ एक सवाल बाकी है क्या आने वाला प्रशासन दिखावे और प्रचार से आगे बढ़कर स्थायी बदलाव की दिशा में काम करेगा, या फिर जिले में अभियान,फोटो और पुरस्कारों की राजनीति ही जारी रहेगी?

मुख्यमंत्री कार्यक्रमों की चूक के बावजूद दोबारा जिला,चर्चा में रहीं चंदन त्रिपाठी

कोरिया जिले की तत्कालीन कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी को बलरामपुर जिले की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं,वजह यह है कि कोरिया में मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी के कार्यक्रमों में कई व्यवस्थागत कमियां सामने आने के बावजूद उन्हें दोबारा जिला मिल गया,मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने मंच से कार्यक्रम में अपेक्षित भीड़ नहीं होने की बात कही थी,वहीं मुख्यमंत्री के कोरिया उत्सव दौरे में अतिथियों के विश्रामगृह आवंटन को लेकर भी अव्यवस्था चर्चा में रही। कार्यक्रम समाप्त होते ही प्रशासनिक तैयारियों की पोल भी खुल गई थी। इसके बाद भी उन्हें नए जिले की जिम्मेदारी मिलना प्रशासनिक चमत्कार की तरह देखा जा रहा है,मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हुई चूक के बाद एक जनपद सीईओ को हटाकर दूसरे अधिकारी को जिम्मेदारी देने का मामला भी चर्चा में रहा,हाईकोर्ट की टिप्पणी के बावजूद मूल सीईओ को प्रभार न दिए जाने को लेकर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठते रहे।

चिड़ियों की तस्वीरों की शौकीन कलेक्टर अब बलरामपुर में पूरा करेंगी अपना शौक

चंदन संजय त्रिपाठी अपने प्रशासनिक कामों के साथ-साथ पक्षियों की फोटोग्राफी के शौक को लेकर भी चर्चा में रही हैं, कोरिया जिले में पदस्थ रहते हुए वे कई बार प्राकृतिक क्षेत्रों में पक्षियों की तस्वीरें खींचती नजर आई थीं,अब उनका तबादला बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में हुआ है,जो घने जंगलों और जैव विविधता के लिए जाना जाता है,झारखंड सीमा से लगे इस वन क्षेत्र में पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं,ऐसे में प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा भी मजाकिया अंदाज में चल रही है कि बलरामपुर जिला उनके लिए प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ-साथ बर्ड फोटोग्राफी का नया केंद्र साबित हो सकता है,कुछ लोग इसे हल्के-फुल्के अंदाज में उनकी नई उपलब्धि भी बता रहे हैं।

कलेक्ट्रेट में चलता था समानांतर प्रशासन?

कोरिया कलेक्ट्रेट में लंबे समय से यह चर्चा आम रही कि जिले में केवल सरकारी प्रशासन ही नहीं,बल्कि एक अनौपचारिक शक्ति केंद्र भी सक्रिय था, आरोप यह लगते रहे कि कुछ चुनिंदा अधिकारी,बाबू, स्टेनो और करीबी कर्मचारी ऐसा प्रभाव रखते थे कि कई मामलों में वास्तविक प्रक्रिया से ज्यादा महत्व उनकी राय को दिया जाता था, सूत्रों की मानें तो यह समूह केवल फाइलों तक सीमित नहीं था,बल्कि कौन अधिकारी कलेक्टर के करीब माना जाएगा और किसकी छवि खराब होगी, यह तय करने में भी भूमिका निभाता था,कई विभागीय अधिकारियों के बीच यह धारणा बन चुकी थी कि काम से ज्यादा पहुंच मायने रखती है,कलेक्ट्रेट में कई बार यह चर्चा सुनाई देती थी कि यदि किसी अधिकारी को अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी है,तो उसे पहले इनर सर्किल की मंजूरी चाहिए, यही वजह रही कि कुछ कर्मचारी और अधिकारी खुद को बेहद प्रभावशाली मानने लगे थे।

चुगली गैंग और स्टेनो लॉबी चर्चा में क्यों?

तबादले के बाद सबसे ज्यादा जिन शब्दों की चर्चा हो रही है,उनमें चुगली गैंग और स्टेनो लॉबी प्रमुख हैं,कलेक्ट्रेट के भीतर यह आरोप लंबे समय से लगाए जाते रहे कि कुछ लोग नियमित रूप से अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतें, गतिविधियां और निजी चर्चाएं ऊपर तक पहुंचाने का काम करते थे। बदले में उन्हें करीबी होने का लाभ मिलता था,हालांकि इन आरोपों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई,लेकिन दफ्तरों में फुसफुसाहट हमेशा बनी रही। कई अधिकारी निजी बातचीत में यह तक कहते रहे कि फाइल से ज्यादा फीडबैक सिस्टम काम कर रहा था,अब जब कलेक्टर का तबादला हो गया है, तो यही लोग सबसे ज्यादा असहज बताए जा रहे हैं,कलेक्ट्रेट में चर्चा है कि नई कलेक्टर अपनी अलग टीम बनाएंगी या पुराने नेटवर्क पर ही भरोसा करेंगी।

बैकुंठपुर स्ष्ठरूसमेत कुछ अधिकारियों की भूमिका पर भी चर्चा

प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा भी समय-समय पर होती रही कि इस पूरे नेटवर्क में कुछ फील्ड अधिकारी भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। विशेष रूप से बैकुंठपुर एसडीएम और कुछ अन्य अधिकारियों के नाम कई बार चर्चाओं में आए,हालांकि इन बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन कर्मचारियों के बीच यह धारणा बनती चली गई कि कुछ अधिकारी मैदानी काम से ज्यादा ऊपरी मैनेजमेंट में सक्रिय रहते थे,यही वजह है कि अब तबादले के बाद लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या नई प्रशासनिक टीम पुराने समीकरणों को जारी रखेगी या फिर पूरी कार्यशैली बदल जाएगी।

आवा पानी झोंकी से राष्ट्रीय पहचान,लेकिन सवाल भी साथ आए

कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के कार्यकाल की सबसे चर्चित उपलब्धियों में आवा पानी झोंकी अभियान रहा। इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया,इसके बाद जिले की प्रशासनिक छवि को लेकर काफी प्रचार हुआ और कोरिया राष्ट्रीय चर्चाओं में आया,समर्थकों ने इसे अभिनव पहल बताया,लेकिन विरोधियों ने इसे इवेंट आधारित प्रशासन कहकर सवाल उठाए,आलोचकों का कहना था कि अभियान का प्रचार ज्यादा हुआ,जबकि जमीनी असर सीमित दिखाई दिया, कई ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट और मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी रहीं। अब तबादले के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह अभियान आगे भी जारी रहेगा या फिर फाइलों और फोटो एल्बम तक सिमट जाएगा।

व्हाट्सएप समूह में बधाई संदेशों ने भी बढ़ाई चर्चा

कलेक्टर कोरिया के तबादले के बाद कुछ अधिकारियों द्वारा व्हाट्सएप समूहों में तत्काल बधाई संदेश दिए जाने की भी खूब चर्चा रही, सामान्यतः किसी अधिकारी के स्थानांतरण पर ऐसी सार्वजनिक सक्रियता कम दिखाई देती है,लेकिन इस मामले में कई संदेश सामने आए, इसे लेकर प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा शुरू हो गई कि यह बधाई केवल औपचारिक नहीं,बल्कि मनचाही पोस्टिंग मिलने की खुशी भी हो सकती है,कुछ लोगों का मानना है कि यह संदेश तत्कालीन कलेक्टर से अधिकारियों की निकटता और उनके प्रायोजित तबादलों की चर्चाओं को भी हवा देते नजर आए।

छवि प्रबंधन बनाम सक्रिय प्रशासन

कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के कार्यकाल को लेकर सबसे बड़ी बहस यही रही कि क्या यह सक्रिय प्रशासन था या छवि आधारित प्रशासन? आलोचकों का आरोप है कि उनके कार्यकाल में बड़े-बड़े आयोजन,स्वागत कार्यक्रम,मीडिया कवरेज और विशेष अभियान पर ज्यादा फोकस रहा। उनका दावा है कि प्रशासनिक छवि निर्माण को प्राथमिकता दी गई,वहीं समर्थकों का कहना है कि उन्होंने जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई,प्रशासन को सक्रिय बनाया और योजनाओं की मॉनिटरिंग को गति दी, यानी एक वर्ग उन्हें ऊर्जावान अधिकारी मानता है,जबकि दूसरा वर्ग इसे ब्रांडिंग आधारित प्रशासन कहता है।

राहुल वेंकट को लेकर भी चर्चा

इस तबादला सूची में स्ष्क्रकलेक्टर राहुल वेंकट का नाम भी चर्चा में है। उन्हें किसी जिले की नई जिम्मेदारी देने के बजाय मंत्रालय भेजा गया है,प्रशासनिक हलकों में राहुल वेंकट को शांत,सरल और नियम आधारित अधिकारी माना जाता रहा है। ऐसे में अब तुलना भी शुरू हो गई है,कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या दिखने वाला प्रशासन ज्यादा महत्व पा रहा है और शांत काम करने वाले अधिकारी पीछे छूट रहे हैं? हालांकि यह पूरी तरह प्रशासनिक और राजनीतिक व्याख्या का विषय है, लेकिन तबादले के बाद ऐसी चर्चाएं तेज होना स्वाभाविक माना जा रहा है।

बलरामपुर में अब कैसी होगी चंदन त्रिपाठी की कार्यशैली?

अब चंदन त्रिपाठी को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की जिम्मेदारी दी गई है, यह जिला प्रशासनिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। आदिवासी क्षेत्र, सीमावर्ती गतिविधियां और विकास की चुनौतियां यहां हमेशा प्रशासन के सामने रहती हैं, अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि वहां उनकी कार्यशैली कैसी रहती है, क्या वहां भी अभियान आधारित प्रशासन देखने को मिलेगा? क्या वहां भी इनर सर्किल जैसी चर्चाएं होंगी? या फिर जमीनी समस्याओं पर ज्यादा फोकस किया जाएगा?

तीन-तीन सुंदर हीरोइन्स के फेर में उलझे आयुष्मान खुराना

पति पत्नी और वो दो का ट्रेलर रिलीज,15 मई को आएगी फिल्म

आयुष्मान खुराना एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी जिंदगी की खलबली लेकर लौट आए हैं। बहुप्रतीक्षित फिल्म पति पत्नी और वो दो का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें आयुष्मान 1-2 नहीं, बल्कि 3-3 हसीनाओं के बीच बुरी तरह फंसे नजर आ रहे हैं। प्यार, शादी और जबरदस्त उलझनों से भरा ये ट्रेलर देख दर्शक खूब ठहाके लगा रहे हैं। फिल्म में आयुष्मान के साथ सारा अली खान,वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगी।बॉलीवुड में एक बार फिर पति की मुसीबतों वाली कहानी की वापसी हुई है। गानों और टीजर के जरिए माहौल बनाने के बाद अब पति पत्नी और वो दो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म की कहानी प्रजापति पांडे (आयुष्मान) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी में एक पत्नी और एक नहीं, बल्कि 2-2 प्रेमिकाएं हैं। इस कन्फ्यूजन और अफरा-तफरी से प्रजापति कैसे बाहर निकलेंगे,यही फिल्म की मुख्य कहानी है।

मुदस्सर अजीज,जिन्होंने पति पत्नी और वो और मेरे हस्बैंड की बीवी जैसी फिल्मों से अपनी खास पहचान बनाई है,एक बार फिर अपनी चिर-परिचित शैली में लौट आए हैं। इस बार भी उन्होंने एक ऐसी कहानी बुनी है,जहां हीरो महिलाओं के चक्कर में बुरी तरह फंसा हुआ है। फिल्म में विजय राज, तिग्मांशु धूलिया और दुर्गेश कुमार जैसे कलाकार भी हैं। टी-सीरीज और बीआर स्टूडियोज के बैनर तले बनी ये फिल्म 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।

बता दें कि पति पत्नि और वो नाम की पहली फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे ने लीड रोल निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और लोगों को खूब पसंद आई थी। बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बाद अब इसी तरह की एक और फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। 15 मई को रिलीज होने वाली इस फिल्म से मेकर्स को अच्छी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि क्या ये फिल्म भी कमाई के मामले में कुछ कमाल कर पाती है या नहीं। ट्रेलर रिलीज होते ही फैन्स का भी इंतजार खत्म हो गया है। फिल्म के ट्रेलर में इसकी कहानी की भी झलक देखने को मिल रही है। फिल्म में दमदार कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। विजय राज जैसे कमाल के कलाकार भी इस फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग का जलवा दिखाते नजर आने वाले हैं।

संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल की बदल सकती है रिलीज तारीख

संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल 8 मई को रिलीज होने के लिए तैयार थी, लेकिन अब ऐसा हो पाना असंभव लग रहा है। खबर है कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की तरफ से रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। पहले ट्रेलर 30 अप्रैल को रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंसर बोर्ड की मंजूरी न मिलने के कारण योजना को स्थगित कर दिया गया। अब फिल्म भी सेंसर से हरी झंडी का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया, फिल्म की प्रकृति और कथानक ऐसा है कि सीबीएफसी के सदस्य सतर्क हैं।

फिल्म निर्माताओं ने सीबीएफसी समिति को समझाया है कि उनकी फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं और अभिलेखों पर आधारित है, इसलिए इसे रिलीज किया जाना चाहिए। फिल्म निर्माताओं और सीबीएफसी के बीच बातचीत में काफी समय लग गया। इसलिए, आखिरी सवाल के निर्माताओं को लग रहा है कि फिल्म को कुछ समय के लिए टाल देना ही समझदारी होगी।सूत्र ने आगे कहा, फिलहाल, फिल्म निर्माता 15 मई को फिल्म रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। बेशक, यह सेंसर की मंजूरी समय पर मिलने पर निर्भर करेगा। सभी बाधाएं दूर होते ही इस संबंध में जल्द ही घोषणा की जा सकती है। राष्टीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता अभिजीत मोहन वारंग द्वारा निर्देशित आखिरी सवाल आरएसएस के 100 साल के इतिहास से प्रेरित कहानी है। इसमें समीरा रेड्डी, अमित साध, नीतू चंद्र और त्रिधा चौधरी जैसे सितारे भी हैं।

सिटाडेल 2 से दिल जीतने आईं प्रियंका चोपड़ा

इन फिल्मों-सीरीज से भी लूटी वाहवाही

प्रियंका चोपड़ा की कामयाबी के चर्चे पूरी दुनिया में गूंजते हैं। यही कारण है कि उनकी हर परियोजना का इंतजार फैंस बेसब्री से करते हैं। 6 मई को अभिनेत्री अपनी चर्चित हॉलीवुड वेब सीरीज सिटाडेल का दूसरा सीजन लेकर आई हैं। इस जासूसी-थ्रिलर का प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया है, जिसमें रिचर्ड मैडेन भी मुख्य किरदार में हैं। आइए जानते हैं प्रियंका की पिछली हॉलीवुड फिल्मों-सीरीज के बारे में, जिन्होंने उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई।

टीवी सीरीज क्वांटिको को प्रियंका के करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसने उन्हें विश्व स्तर पर कामयाबी दिलाने का काम किया। इस सीरीज में उन्होंने एलेक्स पैरिश नाम की एक तेज-तर्रार एफबीआई का रोल निभाया है। उनका अभिनय इतना शानदार रहा कि लगातार 2 साल उन्होंने इसके लिए पीपुल्स चॉइस पुरस्कार जीता। यही नहीं, प्रियंका पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्री बन गईं, जिसने किसी बड़े अमेरिकी टीवी नेटवर्क के शो में मुख्य भूमिका निभाई।

प्राइम वीडियो पर सिटाडेल का पहला सीजन साल 2023 में आया था। यह जासूसी थ्रिलर सीरीज है, जिसमें प्रियंका ने नादिया सिंह का रोल निभाया है, जो सिटाडेल की एक एलीट जासूस है। गेम ऑफ थ्रोन्स वाले अभिनेता रिचर्ड मैडेन भी सीरीज में मुख्य किरदार में हैं। 6 एपिसोड वाली इस सीरीज में, प्रियंका ने अपने अभिनय से ग्लोबल स्तर पर कामयाबी हासिल की। खबरों के मुताबिक, सिटाडेल में उन्होंने करीब 80 प्रतिशत स्टंट खुद किए हैं।

2025 में आई एक्शन-कॉमेडी फिल्म हैड्स ऑफ स्टेट भी प्रियंका के हॉलीवुड करियर में चार चांद लगाने का काम कर चुकी है। इसमें उनके साथ जॉन सीना और इड्रिस एल्बा भी नजर आए थे। यह एक बडी-कॉप फिल्म है, जिसमें कॉमेडी के साथ-साथ हाई-ऑक्टेन एक्शन दृश्य हैं। फिल्म द ब्लफ में, प्रियंका ने पिछले जासूसी किरदारों से बिल्कुल अलग किरदार निभाया है। पूर्व महिला समुद्री डाकू के किरदार में वह तलवारबाजी और पुराने हथियारों का इस्तेमाल करते नजर आईं हैं।

हर वक्त फैसले लेना थका देता है,मीरा राजपूत ने महिलाओं के मानसिक सुकून पर कही दिल की बात

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं कई भूमिकाएं निभाती हैं। ऐसे में मानसिक थकान और दबाव महसूस करना स्वाभाविक है। इसी विषय पर बात करते हुए मीरा राजपूत कपूर ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि महिलाओं को कभी-कभी हर छोटी-बड़ी जिम्मेदारी और फैसलों से दूर होकर खुद के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि वे मानसिक रूप से हल्का महसूस कर सकें। मीरा राजपूत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने मायके में बिताए समय के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, अपने माता-पिता के घर पर रहना एक अलग तरह का सुकून देता है। मायके में मैं खुद को ज्यादा सहज महसूस करती हूं। यहां मुझे किसी तरह का दबाव महसूस नहीं होता। वीडियो में मीरा आगे कहती हैं, काफी समय बाद मैं इस तरह खुलकर अपने मन की बात साझा कर रही हूं। जब मैं अपनी मां के घर पर थी, तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ जगहें और रिश्ते ऐसे होते हैं, जो हमें बिना किसी शर्त के सुकून देते हैं। इस अनुभव को शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है।

मीरा ने कहा, महिलाओं को हर समय फैसले लेने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। दिनभर उन्हें यह तय करना होता है कि घर में क्या बनेगा, कौन कहां जाएगा, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया उन्हें मानसिक रूप से थका देती है। जब कुछ समय के लिए कोई उनसे कुछ नहीं पूछता, तो दिमाग को बहुत राहत मिलती है।

उन्होंने आगे कहा, महिलाएं सिर्फ फैसले ही नहीं लेतीं, बल्कि हर दिन कई विकल्पों में से सही चुनाव भी करती हैं। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और इसका असर मानसिक स्थिति पर पड़ता है। जब किसी महिला को कुछ समय के लिए इन सभी फैसलों और जिम्मेदारियों से छुटकारा मिलता है, तो उसे एक अलग ही तरह की शांति और सुकून महसूस होता है। यही वह समय होता है, जब वह खुद को फिर से ऊर्जा से भर पाती है।

सौंदर्या युवराज का 'आखिरी शरारत' खुलासा

स्प्लिट्सविला 16 का फिनाले बस आने ही वाला है, और कई कंटेस्टेंट बीच-बीच में हिंट या स्पॉइलर देते दिख रहे हैं। सौंदर्या युवराज ने हाल ही में बताया कि दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज इंतज़ार कर रहा है।

उन्होंने फाइनलिस्ट के बारे में भी बात की और शो के विनर पर अपने विचार शेयर किए। रियलिटी स्कूप ने सौंदर्या का एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वह हेयर वॉश सेशन एन्जॉय कर रही हैं। सेशन के दौरान, उनकी देखभाल कर रहे व्यक्ति ने पूछा कि स्प्लिट्सविला 16 में आगे क्या होने वाला है। जवाब देते हुए, सौंदर्या ने कहा,अवि आखिरी शरारत क्या होने वाली है वो भी नहीं पता। इसके साथ,उन्होंने हिंट दिया कि ग्रैंड फिनाले एपिसोड से ठीक पहले एक फाइनल ट्विस्ट या शरारत की उम्मीद है। जब पूछा गया कि स्प्लिट्सविला 16 कौन जीत सकता है, तो सौंदर्या ने कहा,पता नहीं कौन जीतेगा। उन्होंने आगे कहा,जो भी फाइनलिस्ट है उसमें जीत सकता है। इस बीच,अफवाहें हैं कि फिनाले में पहुंचने वाले दो कपल्स योगेश रावत और रुरु ठाकुर, और निहारिका तिवारी और सोरब हैं। फैंस को आने वाले एपिसोड का इंतजार करना होगा कि सफर कैसा होता है।

खेल समाचार

सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब को 33 रन से हराकर किया बड़ा उलटफेर

पॉइंट्स टेबल में बदला समीकरण,आरसीबी को भी लगा झटका

हैदराबाद,07 मई 2026। आईपीएल 2026 के 49 वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रनों से हरा दिया। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मैच में एचआरएच की शानदार बल्लेबाजी के सामने पीबीकेएस की टीम बेबस नजर आई। इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई है।

एसआरएच का दमदार प्रदर्शन

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। हेनरिक क्लासेन ने 43 गेंदों पर 69 रनों की शानदार पारी खेली। उनके अलावा अभिषेक शर्मा ने 35, ट्रेविस हेड ने 38, ईशान किशन ने 55 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 13 गेंदों पर 29 रनों की तूफानी पारी खेली।

पंजाब किंग्स का संघर्ष

जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर सिर्फ 202 रन ही बना सकी। एसआरएच की गेंदबाजी के सामने पीबीकेएस के बल्लेबाज लगातार विकेट गंवाते रहे। इस हार के साथ पंजाब की 13 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है।

पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव

इस जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद 11 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंकों पर पहुंचकर टॉप पर काबिज हो गई है। पंजाब किंग्स 10 मैचों में 6 जीत के साथ 13 अंकों पर दूसरे स्थान पर है। ऋष्क्क 12 अंकों के साथ तीसरे, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस 12-12 अंकों के साथ चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 10 अंकों के साथ छठे स्थान पर है।

ऑरेंज और पर्पल कैप का कब्जा

एसआरएच के हेनरिक क्लासेन ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं। उन्होंने 11 मैचों में 494 रन बना लिए हैं। दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं,जिनके नाम 475 रन हैं। पर्पल कैप के भुवनेश्वर कुमार के पास है, जिन्होंने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। दूसरे स्थान पर चेन्नई के अंशुल कंबोज हैं, जिनके 10 मैचों में 17 विकेट हैं।

प्लेऑफ की दौड़ रोचक

एसआरएच की इस जीत ने प्लेऑफ की दौड़ को और रोचक बना दिया है। अब कई टीमें टॉप-4 में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अगले मैचों में पॉइंट्स टेबल पर और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

हॉकी इंडिया ने भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ -18 सीरीज़ के लिए पुरुष और महिला टीमों की घोषणा की

भोपाल,07 मई 2026। हॉकी इंडिया ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी हाई-इंटेंसिटी सीरीज़ के लिए 24-सदस्यीय भारतीय -18 पुरुष और महिला टीमों की घोषणा की। यह सीरीज़ 15 से 20 मई, 2026 तक भोपाल में स्थित उद्धव दास मेहता (भाई जी) SAI सेंट्रल सेंटर में आयोजित की जाएगी। हॉकी इंडिया की एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, चार मैचों की यह सीरीज़ 29 मई से 6 जून, 2026 तक काकामिगहारा (जापान) में होने वाले पुरुष और महिला -18 एशिया कप के लिए टीमों की अंतिम तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक टीम में अंतिम 24 खिलाड़ियों का चयन नेशनल कोचिंग कैंप के दौरान एक सप्ताह के कड़े मूल्यांकन के बाद किया गया। इस प्रक्रिया में, 42 खिलाड़ियों के शुरुआती समूह को मैच फिटनेस और रणनीतिक अनुकूलन क्षमता के आधार पर छाँटा गया। फॉरवर्ड केतन कुशवाहा को भारतीय -18 पुरुष टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि भारतीय -18 महिला टीम की कप्तानी स्वीटी कुजूर करेंगी। पुरुष सब-जूनियर टीम को पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह और रजनीश मिश्रा द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। आगामी मैचों पर टिप्पणी करते हुए सरदार सिंह ने कहा, ÷कैंप में एक सफल सप्ताह बिताने के बाद, हमने उन 24 खिलाड़ियों की पहचान कर ली है, जिनके बारे में हमारा मानना है कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच केवल अभ्यास खेल नहीं हैं; बल्कि ये हमारे मैच के मिजाज और रणनीतिक अनुशासन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा हैं। केतन मैदान पर एक स्वाभाविक लीडर हैं, और मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि जापान में -18 एशिया कप में जाने से पहले, यह समूह ऑस्ट्रेलियाई शैली के खेल की गति और दबाव को किस तरह संभालता है।÷

36 साल की उम्र में साथी खिलाड़ी के अचानक निधन से टूटे विराट कोहली

युवराज सिंह और शिखर धवन ने भी जताया दुःख

नई दिल्ली,07 मई 2026। भारतीय क्रिकेट के लिए 6 मई का दिन काफी दुखद रहा जिसमें पंजाब की तरफ से घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले पूर्व खिलाड़ी अमनप्रीत सिंह गिल के 36 साल की उम्र में निधन की खबर सामने आई। इतनी कम उम्र में अमनप्रीत सिंह का निधन होना सभी के लिए चौंकाने वाला रहा। अमनप्रीत सिंह गिल एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी थे, जिसमें उन्होंने भारतीय अंडर-19 टीम की तरफ से भी खेला और उस समय उनके साथी खिलाड़ी विराट कोहली भी हुआ करते थे। कोहली भी अपने पुराने साथी प्लेयर के निधन की खबर सुनने के बाद काफी हैरान रह गए जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने दुख को व्यक्त किया है।

अमनप्रीत के निधन की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा है...

अमनप्रीत सिंह गिल का निधन 6 मई की सुबह हुआ था जिसको लेकर पंजाब क्रिकेट संघ ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी और उसी दिन शाम को उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। विराट कोहली ने अमनप्रीत सिंह गिल के निधन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमनप्रीत गिल के निधन की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा है। उनके परिवार और प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति।

भारत अहमदाबाद में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 के पहले संस्करण की मेज़बानी करने के लिए तैयार

अहमदाबाद- वैश्विक योगासन आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में, भारत 4 से 8 जून, 2026 तक गुजरात के अहमदाबाद में ट्रांसस्टेडिया में पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेज़बानी करने के लिए तैयार है, जिसमें 40 से अधिक देशों के एथलीट भाग लेंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार,वर्ल्ड योगासन के तत्वावधान में आयोजित इस चैंपियनशिप की मेज़बानी योगासन भारत करेगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर के शीर्ष एथलीटों को एक मंच पर लाना है, जिससे एक मान्यता प्राप्त प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को बढ़ावा देने में भारत की अग्रणी स्थिति और मज़बूत होगी। इस आंदोलन का उद्देश्य एक ऐसी गूंज पैदा करना है जो वैश्विक स्तर पर बहु-खेल आयोजनों में इस खेल को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करे, और जिसके ओलंपिक खेल बनने की प्रबल संभावना हो।

ऑस्ट्रेलिया का पूर्व खिलाड़ी बनेगा इंग्लैंड टीम का सिलेक्टर

मेलबर्न,07 मई 2026। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को अपनी पुरुष टीम के नए नेशनल सिलेक्टर का ऐलान करना है जिसको लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अभी तक इस पद को उनके पूर्व खिलाड़ी ल्यूक राइट संभाल रहे थे, लेकिन एशेज सीरीज 2025-26 के दौरान पारिवारिक कारणों के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ईसीबी ने खाली हुए पद को लेकर कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, जिसमें इस पद को संभालने के लिए जो नाम सबसे आगे आया है वह इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज मार्कस नॉर्थ का है जो सभी के लिए एक चौंकाने वाली बात जरूर है। वहीं उनकी इस पद पर नियुक्ति आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ जून महीने की शुरुआत में होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले हो सकती है।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी मार्कस नॉर्थ ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद से पिछले काफी सालों से इंग्लैंड में हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अगले सिलेक्टर बनने के लिए मार्कस नॉर्थ की टक्कर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव फिन और डैरेन गॉफ से थी, जिसमें द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इन दोनों को पछाड़ दिया है।

छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई का सीएम हाउस घेराव

पुलिस से झूमाझटकी,कई गिरफ्तार,देवेंद्र यादव बोले...जेल जाओगे तो सांसद-विधायक बनोगे

रायपुर,07 मई 2026। रायपुर में एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया। अलग-अलग जिलों से कार्यकर्ता रायपुर पहुंचे,महिला थाना चौक के पास बने मंच में सभी इकट्ठे हुए और घेराव के लिए निकले। आंदोलन को देखते हुए सीएम हाउस के आसपास 4 लेयर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शनकारी जब बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बीच झूमाझटकी की स्थिति बनी। आरोप है कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर डंडे फेंके। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई के छात्र बड़े वोट से चुनाव जीतेंगे, इस डर से सरकार चुनाव नहीं करा रही है। विधायक देवेंद्र यादव ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से कहा कि जेल जाओगे तो सांसद विधायक बनोगे, सरकार से लड़ने के लिए संघर्ष करो। घेराव के दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई। आखिरी सुरक्षा बैरिकेडिंग के पास पहुंचने से पहले कई नेता गिरफ्तार किए गए हैं।

एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले... सामने आए और सत्ता को चुनौती दें...

एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा- 2018 में राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बना। फिर राजस्थान एनएसयूआई का अध्यक्ष बना और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया गया। मेरे मां बाप मजदूरी करते हैं। जिनके परिवार के लोग दूर दूर तक राजनीति में नहीं है, कांग्रेस पार्टी उन्हें भी मौका देती है। राहुल गांधी चाहते हैं आप लोग भी आए और इस सत्ता को चुनौती दें।

देवेंद्र यादव बोले...जेल जाओगे तो सांसद विधायक बनोगे

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा- विनोग जाखड़ जेल गए तो राहुल गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। आप जेल जाकर लड़ो, राहुल गांधी आपको भी देख रहे हैं। आने वाले समय में विधायक सांसद बनोगे, अपना सपना साकार करोगे।

हाई कोर्ट के 11 अधिवक्ता बने सीनियर एडवोकेट

रजिस्ट्रार जनरल ने जारी की अधिसूचना

बिलासपुर,07 मई 2026। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी कर 11 अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। जारी अधिसूचना में लिखा है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति) नियम, 2025 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सर्वोच्च न्यायालय के 13 मई 2025 के आपराधिक अपील संख्या 865/2025 (जितेंद्र उर्फ कल्ला बनाम राज्य (दिल्ली सरकार)) के निर्णय एवं आदेश के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल 2026 को पूर्ण न्यायालय की स्वीकृति द्वारा निम्नलिखित अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने का संकल्प लिया है।

सीनियर एडवोकेट के रूप में ये हुए नियुक्त

1 शैलेंद्र दुबे 2 रणवीर सिंह मरहस
3 हमीदा सिद्दीकी 4 यशवंत ठाकुर
5 अनूप मजूमदार 6 नीलाभ दुबे
7 अमृतो दास 8 मतीन सिद्दीकी
9 नौशिना आफरीन अली10 अरविन्द श्रीवास्तव
11 तारेन्द्र कुमार झा

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

का प्रदेशव्यापी आयोजन आज

रायपुर,07 मई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में स्थापित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कल 8 मई को प्रदेश के सभी जिलों में भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होगा। इस प्रदेशव्यापी आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और प्रशासनिक अमला वैवाहिक कार्यक्रम की व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटा है। सामूहिक विवाह समारोहों में विभिन्न धर्मों एवं समुदायों के 2300 से अधिक जोड़े अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह सूत्र में बंधेंगे। इस आयोजन में हिंदू, मुस्लिम,ईसाई,बौद्ध सहित विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़ों की सहभागिता,छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता का उदाहरण बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि यह आयोजन केवल विवाह का कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में समानता, सम्मान और एकता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि एक समय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों का विवाह चिंता का विषय होता था,लेकिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने इस चिंता को विश्वास और गरिमा में बदल दिया है। यह योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक संवेदनशील शासन की पहुंच सुनिश्चित करती है। उल्लेखनीय है कि बीते 10 फ़रवरी 2026 को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति में कुल 6,412 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें से 1,316 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद प्रदान किया, जबकि अन्य जिलों के जोड़े वर्चुअल माध्यम से जुड़े इस ऐतिहासिक आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक नवविवाहित दंपति को 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत में संबल मिलता है। इसके साथ ही विवाह आयोजन में आवश्यक सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी जिलों में आयोजन स्थल,भोजन,पेयजल,स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

ताड़मेटला नरसंहार केस में सभी आरोपी दोषमुक्त

हाईकोर्ट बोला...76 जवान शहीद हुए,लेकिन असली कातिलों को पकड़ने में जांच एजेंसियां नाकाम

बिलासपुर,07 मई 2026। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के ताड़मेटला नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान हुए थे। जिसके सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस पर बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि, इतनी बड़ी शहादत के बावजूद अभियोजन एजेंसियां असली अपराधियों की पहचान करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने में पूरी तरह विफल रही हैं। इस तरह हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के दोषमुक्ति के फैसले को सही ठहराया है।

डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि,हमें यह देखकर अत्यंत दुःख हुआ है। बड़े पैमाने पर जवान शहीद हुए और राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। इसके निपटारे में कोई भी कानूनी रूप से मान्य और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका। इसलिए निचली अदालत को उन्हें बरी करने के लिए विवश होना पड़ा। जवानों पर हुए सामूहिक हमले के आरोपियों को प्रत्यक्ष साक्ष्यों की कमी, अपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जांच में प्रक्रियात्मक खामियों और अपराध की गंभीरता के बावजूद उचित संदेह से परे दोष सिद्ध करने में विफलता के कारण बरी कर दिया गया।

सरकार की दलीलें जो कोर्ट में नहीं टिकीं

राज्य के महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने तर्क दिया कि, आरोपी बरसे लखमा का इकबालिया बयान और बरामद पाइप बम पर्याप्त सबूत हैं। साथ ही, घायल जवानों की गवाही न ले पाना एक गंभीर त्रुटि थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इन्हें अपर्याप्त माना क्योंकि इकबालिया बयान किसी स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थित नहीं था।

हाईकोर्ट ने जांच की इन बड़ी खामियों को गिनाया

- किसी प्रत्यक्षदर्शी ने आरोपियों की पहचान नहीं की।
- कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कराई गई।
- एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं की गई।
- जब्त हथियार और विस्फोटक आरोपियों के कब्जे से नहीं मिले।
- शस्त्र अधिनियम के तहत जरूरी अभियोजन स्वीकृति का रिकॉर्ड नहीं था।
- परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला साबित नहीं हो सकी।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दी सख्त नसीहत

डिवीजन बेंच ने कहा कि, भविष्य में ऐसे गंभीर मामलों में जांच के उच्च मानक अपनाने होंगे, ताकि प्रक्रियात्मक चूक के कारण आरोपी बच न सकें। कोर्ट ने कहा कि जांच में फोरेंसिक, तकनीकी और प्राथमिक साक्ष्यों का अभाव न्याय प्रणाली में लोगों के भरोसे को कमजोर करता है।

क्या था मामला ?

6 अप्रैल 2010 की सुबह ताड़मेटला के जंगलों में नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन पर घात लगाकर हमला किया था। इस भीषण नरसंहार में 75 सीआरपीएफ जवान और राज्य पुलिस का 1 सदस्य शहीद हो गए थे। नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए थे।

वंदे मातरम् का सम्मान,राष्ट्रभावना का सम्मान : सीएम विष्णुदेव साय

रायपुर,07 मई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने संबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए इसे देश की सांस्कृतिक चेतना, स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत और राष्ट्रभक्ति की भावना को सम्मान देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और आत्मसम्मान का विषय है। उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम्' भारत की आत्मा, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा और करोड़ों देशवासियों की राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान 'वंदे मातरम्' ने देशवासियों में नई ऊर्जा और आत्मबल का संचार किया था। यह गीत आज भी हर भारतीय के मन में मातृभूमि के प्रति समर्पण, सेवा और गौरव की भावना जागृत करता है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना और अधिक सुदृढ़ होगी।

रायपुर में घर से मिला बम बनाने का रॉ-मटेरियल

एयरगन-बैटरी-कैमिकल बरामद,मितानिन के घर रिश्तेदार ने छोड़ा,कांग्रेस नेता के साले पर शक

रायपुर,07 मई 2026। रायपुर के रावाभाठा इलाके में एक मकान से देसी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला संदिग्ध रॉ मटेरियल, तार और अन्य सामान मिला है। सूचना मिलते ही रायपुर नॉर्थ थाना पुलिस, बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम वार्ड नंबर-13 में मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मौके पर डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जांच के दौरान एक संदिग्ध बैग से बैटरी, वायर, एयरगन, दो बोतल कैमिकल और डेटोनेटर नुमा सामान बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। डीसीपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह सामान विनय देवांगन नाम के शख्स का बताया जा रहा है, जो किसी कांग्रेस नेता का साला है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस जल्द ही मामले में खुलासा करेगी।

मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रविशंकर शुक्ल वार्ड के रावाभाठा इलाके में मितानिन पुष्पा साहू का मकान है। पुष्पा साहू और उनके परिवार का बीरगांव निवासी विनय देवांगन से परिचय है। बुधवार की शाम विनय मितानिन के घर बैग लेकर पहुंचा था। उसने कहा कि वह बैग अभी कुछ समय के लिए यहां रख रहा है और बाद में ले जाएगा। इसके बाद वह वहां से चला गया। मितानिन को इस पर शक हुआ, तो उसने वार्ड पार्षद अश्वनी यादव को सूचना दी।

स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंचे पार्षद : सूचना मिलने पर अश्वनी यादव रात में मितानिन के घर पहुंचे और सुबह आने की बात कहकर वहां से रवाना हो गए। बुधवार की सुबह 8 बजे वार्ड पार्षद स्थानीय रहवासियों के साथ मौके पर पहुंचे और बैग खोलकर जांच की। जांच के दौरान उसमें एयर गन और देसी बम बनाने का सामान मिला। इसके बाद पार्षद ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर नॉर्थ जोन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

मामले की जांच पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस विनय देवांगन का यह सामान बताया जा रहा है, वह कांग्रेस नेता का साला है। पुलिस अब विनय देवांगन से पूछताछ की तैयारी कर रही है।

सर्चिंग में खुल रहे माओवादियों के गुप्त राज

बस्तर में 50 करोड़ से ज्यादा पूंजी छिपे होने का अंदेशा

जगदलपुर,07 मई 2026। बस्तर में माओवादी नेटवर्क के कमजोर पड़ने के साथ अब उनके आर्थिक ढांचे की परतें खुलने लगी है। सुरक्षा बलों की लगातार सर्चिंग में ऐसे डंप सामने आ रहे हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि संगठन सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं बल्कि मजबूत आर्थिक जाल पर भी टिका था। बीते तीन महीनों में जवानों ने करीब 6 करोड़ 75 लाख रुपए नगद और 8 किलो सोना बरामद किया है, जो इस छिपे खजाने की एक झलक भर है। आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक, यह बरामदगी अंदरूनी इलाकों में छिपाकर रखे गए डंप से हुई है, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। जानकार बताते हैं कि नोटबंदी के बाद माओवादियों ने रणनीति बदली और नगद की जगह सोने में निवेश करना शुरू किया, ताकि जोखिम कम रहे। बरामद 8 किलो सोने की कीमत ही करीब 13 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिससे संगठन की आर्थिक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह पैसा तेंदूपत्ता संग्राहकों, ठेकेदारों और विकास कार्यों में लगे लोगों से लेवी के रूप में वसूला जाता था, जो साल दर साल करोड़ों में पहुंचता था। असल में बस्तर में ही माओवादियों की छिपी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। यानी जैसे-जैसे माओवादी नेटवर्क खत्म हो रहा है, वैसे-वैसे उनका आर्थिक साम्राज्य भी उजागर हो रहा है। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि जंगलों में छिपे ऐसे कई डंप अब भी सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। फिलहाल बस्तर में जारी सर्च ऑपरेशन सिर्फ हथियारों की तलाश नहीं, बल्कि माओवादियों की उस आर्थिक रीढ़ को तोड़ने की कोशिश भी है, जिस पर उनका पूरा नेटवर्क खड़ा था।

बिलासपुर में 25 फीट ऊंचाई से गिरकर मजदूर की मौत:बोरा फैक्ट्री में काम करते वक्त हुआ हादसा,प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप

बिलासपुर,07 मई 2026। बिलासपुर में बोरा फैक्ट्री में काम करते समय एक मजदूर 25 फीट की ऊंचाई से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटना सीपत थाना क्षेत्र की है। ग्राम जांजी निवासी लक्ष्मी प्रसाद धीवर (45) सोमवार सुबह रोज की तरह काम करने पहुंचा। दोपहर करीब 3 बजे वह प्लांट में ऊंचाई पर चढ़कर सफाई कर रहा था। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से करीब 25 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि ऊंचाई में काम करते समय उसे कोई सेफ्टी उपकरण नहीं दिया गया था, जिससे हादसा और गंभीर हो गया। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई। प्रबंधन द्वारा घायल मजदूर को तुरंत श्री राम केयर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई।

1.14 करोड़ का गांजा जब्त : सब्जी के खाली कैरेट के पीछे छिपाकर की जा रही थी तस्करी,दो तस्कर गिरफ्तार

महासमुंद,07 मई 2026। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टीम ने एक पीकअप वाहन से 1.14 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त किया है, जिसे खाली कैरेट के पीछे छिपाया गया था और ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। इसी के साथ ही टीम ने दो तस्करों को भी पकड़ा है। यह पूरा मामला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का है। दरअसल, एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स की ओर से अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी, एंड टू एंड एवं फाइनेशियल, सोर्स प्वाइंट, डेस्टीनेशन प्वाइंट पर प्रभावी और विधिवत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत जिले में पुलिस की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच टीम को सूचना मिली कि तस्कर पीकअप क्रमांक MH16CD8741 में ओडिशा की ओर से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं, जिसके बाद टीम ने गनियारीपाली गांव NH 53 रोड सिल्की ढाबा के सामने नाकेबंदी की। इस दौरान टीम ने मुखबिर के बताए पीकअप को रोक लिया और उसकी तलाशी लेने पर डाला में खाली कैरेट के बीच बोरियों में 226.600 किलोग्राम गांजा मिला, जिसकी कीमत 1 करोड़ 14 लाख 30 हजार रुपए आंकी गई। वही टीम ने वाहन सवार दो तस्कर को भी पकड़ा, जिन्होंने अपना नाम अजिनाथ आश्रु जाधव (28) और अक्षय बारुक (32) बताया। दोनों महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले हैं। इसी के साथ ही आरोपियों ने बताया कि वो गांजा को ओडिशा के बालिगुड़ा से अहमदनगर लेकर जा रहे थे।

अफीम की खेती का खुलासा करने वाला सरपंच बर्खास्त

चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामला छिपाया,2 महीने पहले बीजेपी नेता के खिलाफ की थी शिकायत

दुर्ग-भिलाई,07 मई 2026। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले अफीम की खेती का खुलासा दुर्ग जिले में हुआ था। इसकी शिकायत समोदा गांव के सरपंच अरुण गौतम ने की थी। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार को अफीम की खेती करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं,अब अफीम की खेती की शिकायत करने वाले समोदा गांव के सरपंच अरुण गौतम को बर्खास्त कर दिया गया है। एसडीएम कोर्ट ने उन्हें चुनावी हलफनामे में हत्या के प्रयास का मामला छिपाने का दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सरपंच पद से हटाने का आदेश दिया है। अब समोदा गांव में सरपंच पद के लिए दोबारा उपचुनाव कराया जाएगा। कोर्ट ने दुर्ग जनपद पंचायत के सीईओ को राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

2 महीने पहले ही बीजेपी नेता के खिलाफ की थी शिकायत : समोदा गांव के सरपंच अरुण गौतम ने करीब दो महीने पहले, होली के बाद बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम की खेती होने की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। वहीं, विनायक ताम्रकार ने भी सरपंच अरुण गौतम के खिलाफ चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामला छिपाने की शिकायत की थी। दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद बना हुआ है।

चुनाव हारने वाली प्रत्याशी ने सरपंच के खिलाफ लगाई थी याचिका : सरपंच अरुण गौतम को उनके पद से हटा दिया गया है। एसडीएम (राजस्व) कोर्ट ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया है। अरुण गौतम ने साल 2025 के पंचायत चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास (धारा 307) समेत अन्य मामलों की जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी थी। इस मामले को लेकर चुनाव में दूसरे स्थान पर रहीं प्रत्याशी भुवनेश्वरी देशमुख ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। शुरुआत में रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से सुनवाई के लिए इसे दोबारा एसडीएम कोर्ट भेजा गया। एसडीएम कोर्ट में दस्तावेजों की जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि अरुण गौतम के खिलाफ दुर्ग कोर्ट में पहले से एक गंभीर आपराधिक मामला लंबित था। इसके बावजूद उन्होंने चुनावी हलफनामे में इस जानकारी को छिपाया था।

कोर्ट ने समोदा का सरपंच पद रिक्त घोषित किया : एसडीएम कोर्ट ने कहा कि चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाना नियमों का उल्लंघन है। इसी आधार पर कोर्ट ने अरुण गौतम का चुनाव शून्य घोषित करते हुए समोदा गांव का सरपंच पद रिक्त घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता भुवनेश्वरी देशमुख ने मांग की थी कि उन्हें सरपंच घोषित किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में अरुण गौतम को 869 वोट मिले थे, जबकि भुवनेश्वरी देशमुख को 741 वोट प्राप्त हुए थे।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)